सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com  Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in  Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 338 नई दिल्ली, गुरूवार 12 नवम्बर-2026 | नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित | ` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

# सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक जारी रखने को दी मंजूरी

## इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद

**नई दिल्ली.एजेंसी**



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पांच वर्षों के लिए यानी 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपए का ऋण गारंटी कोष बनाया गया है।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस पहल के माध्यम से 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इससे उन्हें नए उद्यम स्थापित करने और आर्थिक अवसरों का विस्तार करने में सहायता मिली है।

बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसमें आगे कहा गया, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से अधिक महिला/एससी/एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता कंपोजिट लोन के रूप में उपलब्ध है, जिसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों शामिल होते हैं।

इसके अलावा, केवल सावधि ऋण भी लिया जा सकता है। वित्तीय सहायता परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकती है। बयान में कहा गया, 10 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपये तक की राशि के लिए ऋण कंपोजिट (कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण) या सावधि ऋण के रूप में लिया जा सकता है। यह परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकता है। इस योजना के दायरे में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इससे वंचित समुदायों के उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी का अवसर मिलता है। संस्थागत ऋण तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए इस योजना के तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी उपलब्ध कराई जाती है, जबकि सामान्य गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम को जारी रखने से औपचारिक ऋण तक पहुंच बेहतर होगी और नए उद्यमों की स्थापना को समर्थन मिलेगा। इससे महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

### केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारम्भ के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने देश में पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

# प्रधानमंत्री मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे

## मोदी बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे

**नई दिल्ली.एजेंसी**



**• प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, आधारशिला और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे**
**• प्रधानमंत्री, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशनों - चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगे**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे। वे 13 नवंबर को बेंगलुरु में सुबह लगभग 10:45 बजे प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दोपहर प्रधानमंत्री तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें सफर करेंगे।

दोपहर लगभग 1:15 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे जहां दोपहर लगभग 3:30 बजे वे भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम लगभग 4 बजे, प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

14 नवंबर को, प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अंबाजी मंदिर 51 पूजनीय शक्तिपीठों में एक है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर स्वर्ण जयंती प्रशासनिक खंड का शिलान्यास करेंगे और तिरुवनंतपुरम, केरल में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस (मुख्य परिसर से बाहर स्थित केंद्र) का शुभारंभ करेंगे।

13 से 23 नवंबर 2026 तक विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर आयोजित होने वाला यह स्वर्ण जयंती समारोह संस्था-निर्माण और सेवा के पांच दशकों का प्रतीक है। 1975 में स्थापित, प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एस-व्यासा का केंद्र है, जिसे 2002 में मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और यह योग में शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है।

इस कार्यक्रम में 1926 में बेंगलुरु में जन्मे प्रख्यात विचारक, लेखक और संगठनकर्ता होंगसांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्रि जी की जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी।

# बीकानेर में दर्दनाक हादसा : डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत, बचाने के प्रयास में गई जान



**बीकानेर.एजेंसी**

राजस्थान के बीकानेर जिले में बुधवार को एक हृदयविदारक हादसा हो गया। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के 4 एडब्ल्यूएम इलाके में पानी की डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतकों में 14 वर्षीय पूजा सहित मुकेश, मनोज और निर्मल शामिल हैं। एक को बचाने के लिए तीन अन्य भी कूदे प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह पूजा नायक खेत में बनी डिग्गी से पानी निकाल रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी। बहन को डूबता देखकर उसके दोनों भाई मुकेश और मनोज उसे बचाने के लिए डिग्गी में कूद गए। इसी दौरान कालूराम का बेटा निर्मल भी उन्हें बचाने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन पानी की गहराई के कारण चारों बाहर नहीं निकल सके। हादसे में जान गंवाने वाले चारों बच्चे दो सगे भाइयों के परिवार से थे।

इनमें रमेश नायक के तीन बच्चे और कालूराम का एक बेटा शामिल था। एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि छतरगढ़ थाने से करीब दो किलोमीटर दूर सोना राम मेघवाल का खेत है, जिसे रमेश नायक ने लीज पर ले रखा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंचने तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य तीन को बेहद कमजोर नब्ज की स्थिति में अस्पताल ले जाया गया।

# उपराष्ट्रपति की तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के 105वें स्थापना दिवस समारोह में गरिमामयी उपस्थिति

**तूतुकुडी.एजेंसी**




**-> टीएमबी की 105 साल की यात्रा विश्वास, सेवा और वित्तीय समावेशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण**
**-> विकसित भारत @2047 को साकार करने के लिए बैंकों को एमएसएमई, किसानों, उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का समर्थन करना चाहिए**

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की तूतुकुडी में तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) के 105वें स्थापना दिवस समारोह में गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उन्होंने आने वाले वर्षों में इस बैंक से भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक बनने की आकांक्षा रखने का आह्वान किया।

बैंक को उसकी 105 साल की उल्लेखनीय यात्रा के लिए बधाई देते हुए, उपराष्ट्रपति ने 1921 में नादर बैंक लिमिटेड के रूप में इसकी उत्पत्ति को याद किया और देश के बैंकिंग क्षेत्र में इसके योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि, अपनी साधारण शुरुआत से, बैंक 17 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 632 शाखाओं के साथ एक प्रमुख बैंकिंग संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, जो 53 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है और कुल कारोबार 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक दर्ज कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने एमएसएमई, किसानों, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और कॉरपोरेट जगत को जिम्मेदार ऋण देने और वित्तीय सहायता देने के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया और कहा कि विकसित भारत ञ्च2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई द्वारा लाए गए परिवर्तन के साथ-साथ वित्तीय समावेशन के विस्तार पर प्रकाश डाला, जिसने अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है।

टीएमबी के हालिया प्रदर्शन और तकनीकी प्रगति की सराहना करते हुए, उन्होंने बैंक से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, ग्राहकों के पैसे और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने और नवाचार को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंक को अपने मूल स्थान तूतुकुडी में निहित रहना चाहिए, भले ही यह अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार करे। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक अधिक ऊंचाइयों को छूना जारी रखेगा और भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच खुद को स्थापित करेगा।

# स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 : चंडीगढ़ देश में दूसरे स्थान पर, कचरा प्रबंधन और जनसहभागिता ने दिलाई बड़ी कामयाबी

**चंडीगढ़.एजेंसी**



'सिटी ब्यूटीफुल' के नाम से विख्यात चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वच्छता और सुनियोजित शहरी प्रबंधन का लोहा एक बार फिर मनवाया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 'स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26' के राष्ट्रीय परिणामों में चंडीगढ़ ने 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में समूचे देश में दूसरा स्थान हासिल कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।

इस शानदार प्रदर्शन से न केवल शहर की राष्ट्रीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के साझा प्रयासों पर भी मुहर लगी है। नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विगत वर्षों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण और डड्डुमाजरा स्थित लीगेसी वेस्ट (पुराने कचरे के पहाड़ों) के तीव्र निस्तारण पर विशेष फोकस किया गया था। इसी सतत प्रयास का सुखद परिणाम है कि शहर ने शीर्ष तीन स्वच्छ शहरों में अपनी जगह पक्की की। सर्वेक्षण के दौरान केंद्र सरकार की स्वतंत्र मूल्यांकन टीमों ने कचरा प्रसंस्करण क्षमता, सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई, सीवरेज शोधन, वायु गुणवत्ता सुधार और आम नागरिकों के प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर अंक प्रदान किए, जिसमें चंडीगढ़ ने अधिकांश मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस सफलता का मुख्य आधार नागरिकों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, व्यापार मंडलों और सफाई मित्रों की दिन-रात की मेहनत रही है।

# मदर डेयरी ने दूध के दाम दो से चार रुपये प्रति लीटर बढ़ाए, आज से नई दरें होंगी लागू

**नई दिल्ली (एजेंसी)**



**दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने इससे पहले 14 मई, 2026 को कीमतें बढ़ाई थीं। उससे पहले अप्रैल, 2025 में कीमतों में संशोधन किया गया था**

मदर डेयरी ने बढ़ती लागत के कारण दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरें आज से लागू होंगी। दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने इससे पहले 14 मई, 2026 को कीमतें बढ़ाई थीं। उससे पहले अप्रैल, 2025 में कीमतों में संशोधन किया गया था। सूत्रों के अनुसार, मदर डेयरी ने अपने खुले दूध की विभिन्न किस्मों के उपभोक्ता कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने हालांकि इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि किसानों से दूध की खरीद की कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण कंपनी को लागत में हुई वृद्धि का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है। मदर डेयरी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है। कंपनी दिल्ली-एनसीआर बाजार में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है।

कुल मिलाकर, कंपनी प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में टोंड दूध (थोक वितरण) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। फुल क्रीम दूध (पाउच) की कीमत अब 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर होगी। टोंड दूध (पाउच) की कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर होगी। गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। केवल छह महीने में दूध की कीमतों में हुई इस वृद्धि से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा और खाद्य महंगाई भी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, खाद्य महंगाई सितंबर में बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 5.97 प्रतिशत थी। सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, प्याज और अन्य खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण खुदरा महंगाई सितंबर में तेजी से बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई।

# हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्थापित की जाएंगी स्पेशल न्यायालय

**कदम सिंह/ओपन सर्च ब्यूरो**



**पांच जिलों में स्थापित होंगी स्पेशल न्यायालय**
एससी-एसटी से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करने की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जाए।

**चंडीगढ़।** हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शत-प्रतिशत मामलों में इस समय-सीमा का पालन हो। पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतू राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग 28% तक की कमी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एससी-एसटी से संबंधित मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और इसे शत-प्रतिशत ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के मामलों में 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही, जिला एवं उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की प्रगति, जांच और समयबद्ध निपटान की नियमित निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

## लोकसभा अध्यक्ष ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पुष्पांजलि अर्पित की

**नई दिल्ली.ओपन सर्च**

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसद सदस्यगण एवं पूर्व संसद सदस्यों ने भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह तथा राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी ने भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन-वृत्त पर आधारित पुस्तिका भी भेंट की गई।

# विकास कार्यों के टेंडर में तेजी के लिए अलग कॉरपोरेशन बनाया जाए : सीएम

## सरकार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को दे रही सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री नायब सैनी

ओपन सर्च ब्यूरो



**चंडीगढ़।** हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि महत्वपूर्ण विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को तेजी से सिरे चढ़ाने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर अलग से कॉरपोरेशन बनाया जाए जो सभी विभागों के बड़े व महत्वपूर्ण टेंडरों की प्रक्रिया को बिना देरी पूरा करवाए। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और बजट का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के विभागवार खर्च की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने सभी विभागों को अलॉट किए गए बजट के खर्च की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाया जाए ताकि अलॉट किए गए बजट का चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समुचित उपयोग हो सके। समीक्षा बैठक में कुछ विभागों के टेंडरों में देरी का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की प्रवृति के अनुरूप नया कॉरपोरेशन बनाने के साथ-साथ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने तथा टाउनशिप कंसल्टेंट हायर करने के विकल्प अपनाए जाएं। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़े विभागों के अधिकारी समुचित योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि विभागों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर टेंडर अलॉट करने तक की प्रक्रिया कॉरपोरेशन व विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स के माध्यम से होगी तो टेंडर प्रक्रिया तेज गति से पूरी हो सकेगी जिससे विकास कार्यों का आमजन को त्वरित लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था। अधिकारी चालू वित्त वर्ष में प्राप्त बजट के शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखें। समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभागवार खर्च की स्थिति के अनुसार, 13 विभाग अपने वार्षिक बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत व्यय के साथ अग्रणी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 73.7 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग ने 68.6 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत बजट का उपयोग किया है। इसी प्रकार, पुलिस विभाग द्वारा 61 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा 58.7 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 55.7 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बजट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। चालू कार्यों के संपन्न होने के साथ ही बजट के खर्च की गति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रदर्शित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का विकास कार्यों में समुचित इस्तेमाल करने के मामले में सभी विभाग प्रो-एक्टिव होकर कार्य करें। इसी प्रकार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से भी किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। नायब सैनी ने कहा कि वे दिसंबर के अंत में पुनः बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे। तब तक किसी विभाग का खर्च 90 प्रतिशत से कम न हो।

उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष प्रदेश में पराली जलने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं। इसी प्रकार इस वर्ष गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहने और चीनी उत्पादन बढ़ने के आंकड़ों पर भी मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ व ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो-तीन खेल स्टेडियम बनवाए जाएं। उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए बनवाए जाने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बजट में निर्धारित प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण की भावना के साथ हो, ताकि प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिले और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार किया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, एके सिंह, विजयेंद्र कुमार, प्रधान सचिव पंकज यादव, विजय सिंह दहिया, आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, सीजी रजनीकांथन व हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

## विष्णु दत्त का धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 के लिए चयन

ओपन सर्च ब्यूरो



**चंडीगढ़।** हरियाणा की समृद्ध लोकनाट्य परंपरा सांग को समर्पित प्रतिष्ठित धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 के लिए प्रसिद्ध सांगी पंडित लख्मीचंद के पौत्र विष्णु दत्त का चयन किया गया है। उन्हें एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि हरियाणा की लोक संस्कृति में सांग का विशेष स्थान है।

यह केवल मनोरंजन की विधा नहीं, बल्कि लोक जीवन, सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम रही है। सांग की इसी गौरवशाली विरासत के संरक्षण एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय सांग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के राज्य स्तरीय सांग महोत्सव का आयोजन 23 से 27 फरवरी, 2026 तक हरियाणा कला परिषद, कुरुक्षेत्र के सभागार में किया गया था।

पांच दिवसीय महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न सांग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणा की पारंपरिक लोकनाट्य शैली, लोक संगीत, अभिनय और संवाद अदायगी की समृद्ध झलक प्रस्तुत की। डॉ. दहिया ने बताया कि पुरस्कार के लिए निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अंतर्गत समीक्षा समिति द्वारा कलाकारों की मंचीय प्रस्तुतियों का मूल्यांकन 60 अंकों तथा चयन समिति द्वारा उनके दस्तावेजों एवं जीवनवृत्त का मूल्यांकन 40 अंकों के आधार पर किया गया। दोनों समितियों के संयुक्त मूल्यांकन के उपरांत विष्णु दत्त का इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयन किया गया।

**पंडित लखमीचंद की गौरवशाली सांग परंपरा से जुड़ा है विष्णु दत्त का नाम**

डॉ. आदित्य दहिया ने कहा कि हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा में पंडित लख्मीचंद का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अपनी रचनाओं, लोकगीतों और सांग प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणवी लोक साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। उनकी रचनाओं में लोकजीवन की संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार, नैतिक मूल्य और मानवीय संबंधों की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है।

## हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर तक बढ़ीं

ओपन सर्च ब्यूरो



**चंडीगढ़।** हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की अनुबंध अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी है। अब इन कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर, 2026 तक जारी रहेंगी। यह विस्तार 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की अनुबंध अवधि पहले 31 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई गई थी। अब सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए इसे आगामी दो माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों में तैनात कर्मचारियों की अनुबंध अवधि भी दो माह के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार एचकेआरएन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही होगा। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों, बोर्डों एवं निगमों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

## लाइब्रेरी और शिवधाम के कार्य 15 नवंबर तक करें पूरा : उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो



**करनाल।** उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि जिला में लाइब्रेरी व शिवधाम के कार्य को 15 नवंबर तक पूरा करें । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में तेजी लाए तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और हर सप्ताह ग्राउंड पर प्रगति नजर आए। उपायुक्त ने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिए कि भवन बनाने तक सभी लाइब्रेरियों के लिए किताबें और फर्नीचर की व्यवस्था करें। डीसी ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में उक्त परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की और कहा कि सभी परियोजनाएं आमजन व युवाओं की सुविधाओं से संबंधी है, इनकी गंभीरता को समझें और इन्हें प्राथमिकता दें। कहीं पर भी ढिलाई न बरतें। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे फील्ड विजिट करे और कार्यों की प्रगति पर जायजा ले। जहां पर अब तक कार्य शुरू नहीं हुए है, उन्हें जल्द शुरू करवाएं। इन कार्यों को पूरा करवाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। किसी भी गाँव में फण्ड की कोई दिक्कत नहीं होगी, एमपी लैड फंड की उपलब्धता भी इन कार्यों को पूरा करने है।

इन कार्यों में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भी कार्य शामिल करने के निर्देश दिए। सीईओ जिला परिषद अमित खोखर ने बैठक में बताया कि 128 गाँव में लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी है, 53 अन्य में भी कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष में कार्य प्रगति पर है। लाइब्रेरियों के लिए किताबों और फर्नीचर के लिए मुख्यालय को पत्र लिख दिया गया है।कुछ लाइब्रेरियों के लिए फर्नीचर विभाग द्वारा उपलब्ध भी करवा दिया गया है। बैठक में एडीसी डा. राहुल रईया, जिला परिषद के सीईओ अमित कुमार,डीडीपीओ कंचन लता, परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार, सहायक परियोजनाओं अधिकारी जितेंद्र कुमार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और सभी खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे।

## कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 प्लस 2 ड्यूल डिग्री प्रोग्राम का प्रस्ताव

### हरियाणा के जे.सी. बोस विश्वविद्यालय और रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के बीच ड्यूल डिग्री और यूरोपियन मोबिलिटी पर सहमति

ओपन सर्च ब्यूरो

**चंडीगढ़।** हरियाणा के जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के छात्रों के पास जल्द ही अपनी इंजीनियरिंग की आधी डिग्री यूरोपीय संघ में पूरी करने का सीधा अवसर होगा। अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय ने रोमानिया की प्रतिष्ठित टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के साथ 2 प्लस 2 ड्यूल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में कार्य-योजना तैयार की है।

इस प्रस्तावित सहयोग के अंतर्गत कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को भारतीय और यूरोपीय विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। इसके साथ ही विद्यार्थी एवं संकाय आदान-प्रदान तथा संयुक्त नवाचार एवं अनुसंधान कार्यक्रमों पर भी सहमति बनी है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कुलसचिव प्रो. अजय रँगा और प्रो. संजीव गोयल, जो वर्तमान में यूरोप के दौरे पर है, ने रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के साथ ड्यूल डिग्री, फैकल्टी एवं स्टूडेंट एक्सचेंज, स्कॉलरशिप और संयुक्त नवाचार कार्यक्रमों को लेकर रणनीतिक चर्चा की। दोनों पक्षों में सहमति के अनुरूप दोनों विश्वविद्यालय कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 प्लस 2 ड्यूल डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसके तहत छात्र दो साल की पढ़ाई फरीदाबाद में और दो साल क्लुज-नापोका में पूरी करेंगे।

## गौवंश के लिए चारा अनुदान हेतु अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित

### पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत : कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा

ओपन सर्च ब्यूरो



**चंडीगढ़।** हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है , इसीलिए पशुपालन को प्रोत्साहन देने और किसानों की आजीविका के नए आयाम समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, तथा राज्य सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राणा ने बताया कि राज्य की पंजीकृत गौशालाओं और नंदीशालाओं के गौवंश के साथ-साथ पुनर्वसित गौवंश के लिए चारा अनुदान हेतु अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, दुग्ध प्रसंस्करण और पोषण को बढ़ावा देने के लिए पिस्ता और केसर फ्लेवर में दूध, जौ-ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और मैंगो लस्सी जैसे पौष्टिक उत्पादों को भी लॉन्च किया गया है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसी कड़ी में सहकारी समिति स्तर पर दूध ठंडा करने के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2024-26 के दौरान 80 'बल्क मिल्क कूलर' आवंटित किए गए हैं। उन्होंने पशु नस्ल सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि हिसार में लगभग 18.63 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक सैक्स-सोर्टिड सीमन प्रयोगशाला (Se&-Sorted Semen Laboratory) स्थापित की गई है।

इसके अलावा, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' के तहत अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 तक लगभग 51,000 लाभार्थियों के खातों में 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि हस्तांतरित की गई है। राणा ने कहा कि सरकार के इन निरंतर प्रयासों से राज्य में पशुपालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।

## राज्य भर में खुलेंगी 2,651 फेयर प्राइस शॉप्स, इच्छुक आवेदक 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

ओपन सर्च ब्यूरो

**चंडीगढ़।** हरियाणा सरकार ने गरीब और पात्र परिवारों के लिए राशन डिपो की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राज्यभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा, जहां मौजूदा डिपो काफी दूर स्थित हैं। इस योजना से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 10 अक्टूबर 2026 को की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि योग्य आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

## नाम बदलने, घोषणाओं से नहीं, परियोजनाएं पूरी करने से होगा देश का विकास : कुमारी सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो



**सिरसा।** सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में आरंभ की गई विकास योजनाओं के नाम और स्वरूप बदलकर उन्हें नई उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करने की राजनीति से देश का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की परियोजना निगरानी संबंधी अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित प्रकाशित समाचार के अनुसार 1,853 बड़ी परियोजनाओं की लागत में लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें 25 मेगा परियोजनाओं की लागत ही करीब 2.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है। यह स्थिति सरकारी निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के बाद भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को बड़े प्रचार के साथ प्रस्तुत किया। लेकिन भारी धनराशि खर्च होने के बावजूद अनेक शहरों में बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी हुई, कितना धन खर्च हुआ और नागरिकों को वास्तविक लाभ कितना मिला। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पिछले लगभग 12 वर्षों से अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री लगातार नई घोषणाएं करते हैं, लेकिन अनेक घोषणाओं का धरातल पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देता। सड़कों, पेयजल, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में देरी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस की नीति पारदर्शी प्रशासन, जनकल्याण और जवाबदेह विकास की रही है।

## एसडीडी मतदाताओं के भौतिक सत्यापन कार्य में सहयोग करने के लिए एसडीएम ने की सभी राजनैतिक दलों से अपील

ओपन सर्च ब्यूरो



**सोनीपत।** मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है।

इसी कड़ी में बुधवार को लघु सचिवालय में एसडीएम सुभाष चंद्र ने विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिले में एएसडीडी श्रेणी में शामिल 2 लाख 36 हजार 651 मतदाताओं को दोबारा एन्यूमरेशन फार्म (गणना प्रपत्र) वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) दोबारा घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। एसडीएम सुभाष चंद्र ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रहे। इसके लिए एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की पहचान कर उनका दोबारा सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने बूथ स्तर एजेंटों के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को तलाशने में बीएलओ का सहयोग करें, ताकि पात्र मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने बताया कि एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की सूचियां सीईओ हरियाणा की वेबसाईट और सभी मतदान केन्द्रों पर चस्पा की जा चुकी हैं। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता को सूची में शामिल किसी नाम को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह संबंधित बीएलओ के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

**प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए बीएलओ दोबारा घर-घर जाकर करेंगे एएसडीडी सूची में शामिल मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कार्य-एसडीएम सुभाष चंद्र**

एसडीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग करें और अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें।

उन्होंने अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिए कि वे घर-घर जाकर संपर्क स्थापित करें और प्रत्येक पात्र मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से पुनरीक्षण कार्य पूरा हो और कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। एसडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि एएसडीडी श्रेणी के मतदाताओं के गणना प्रपत्र सभी बूथ स्तर अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

# दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, बच्चों पर सबसे ज्यादा असर

नई दिल्ली (एजेंसी)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों (एनसीआर) में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। प्रदूषण के कारण न केवल सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि इसका असर हृदय, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है।

विशेषज्ञ के मुताबिक, प्रदूषण के अलग-अलग घटक शरीर को अलग-अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। बड़े कण त्वचा, आंखों और नाक में जलन पैदा करते हैं, जबकि जहरीली गैसें शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) और ऑक्सीजन की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। वहीं, पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों के भीतर तक पहुंचकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा का अटैक पड़ सकता है और सीओपीडी के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों में लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आशंका भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञ ने कहा कि प्रदूषण का असर केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से चिड़चिड़ापन, तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही मस्तिष्क की कार्यक्षमता यानी कॉग्निटिव फंक्शंस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञ ने कहा कि वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि उनके फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं। समय से पहले जन्मे (प्रीमैच्योर) बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए प्रदूषण का जोखिम और अधिक गंभीर हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के प्रदूषण के संपर्क में आने से गर्भस्थ शिशु के फेफड़ों के विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 11 साल तक कम होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में यह केवल स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी चिंता है। प्रदूषण से बचाव के उपायों पर विशेषज्ञ ने कहा कि सबसे बेहतर तरीका प्रदूषण के संपर्क को कम करना है। लोगों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जिनसे प्रदूषण बढ़ता है।

घरों में बायोमास ईंधन जलाने से बचना चाहिए और वाहनों की नियमित सर्विसिंग करानी चाहिए, ताकि उनसे निकलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि मेट्रो और बसों जैसी सुविधाओं को इतना बेहतर बनाया जाना चाहिए कि लोगों को निजी वाहनों का इस्तेमाल करने की जरूरत कम पड़े। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों को भी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना चाहिए।

## तीन साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण : सीएसई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों और पराली के धुएं को जिम्मेदार ठहराने के बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट ने प्रदूषण पर नई तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा जहरीली हो चुकी थी।



**सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा**

दिवाली से पहले वाले सप्ताह में पीएम2.5 का औसत स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो 2025 के मुकाबले 97 फीसदी और 2024 के मुकाबले 32 फीसदी अधिक है। यह तीन वर्षों का सर्वाधिक स्तर है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की जहरीली हवा के पीछे केवल पराली और पटाखे नहीं, बल्कि साल भर जारी रहने वाला शहरी प्रदूषण और वाहनों का उत्सर्जन बड़ी वजह है।

**पराली और पटाखों के अलावा भी अन्य से फैला प्रदूषण?**

स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों में वाहनों की हिस्सेदारी 52 फीसदी है। वहीं, पड़ोसी एनसीआर जिलों से आने वाला प्रदूषण दिल्ली के कुल पीएम2.5 में 54.43 फीसदी योगदान दे रहा है। सीएसई ने साफ कहा है कि आपातकालीन पाबंदियां भी सड़कों पर जाम कम करने में नाकाम रही हैं।

## 'तप और दीक्षा से ही राष्ट्र, बल और सामर्थ्य की हुई उत्पत्ति', पीएम मोदी ने साझा किया सुभाषित

नई दिल्ली (एजेंसी)



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया है। इस सुभाषित के जरिए संदेश दिया है कि तप और दीक्षा से ही राष्ट्र, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति होती है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर संस्कृत श्लोक, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे। ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु।' साझा किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि सबके कल्याण की इच्छा करने वाले, स्वर्ग के ज्ञाता ऋषियों ने सबसे पहले तप और दीक्षा का आश्रय लिया।

उस तप और दीक्षा से ही राष्ट्र, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। ऐसे विकासोन्मुखी राष्ट्र और उसकी सामर्थ्य को सभी देवता नमन करते हैं। यह मंत्र अथर्ववेद (शौनक संहिता, काण्ड 19, सूक्त 41, मंत्र 1) से लिया गया है। यह मंत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक सशक्त, ओजस्वी और समृद्ध राष्ट्र की नींव भोग-विलास से नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, अनुशासन और सामूहिक कल्याण की भावना से होती है। इसमें ऋषियों (द्रष्टाओं और मार्गदर्शकों) के संकल्प को राष्ट्र के निर्माण और उसकी ऊर्जा (बल और ओज) का मूल स्रोत बताया गया है। बता दें कि अथर्ववेद-संहिता हिन्दू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद, अथर्ववेद, की संहिता, अर्थात् मंत्र-भाग है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति-स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवरहित होकर निरन्तर उन्नति करता जाता है।

## छठ पूजा के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट और संबंधित कोर्ट में भी 16 नवंबर को रहेगा अवकाश

नई दिल्ली (एजेंसी)



छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य संबंधित कोर्ट में भी 16 नवंबर को अवकाश रहेगा। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पोस्ट के जरिए दी। अवकाश के संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, छठ पूजा के कारण सोमवार, 16 नवंबर 2026 को हाई कोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालयों में अवकाश घोषित किया गया है। सोमवार के अवकाश के बदले तीसरे शनिवार, 21 नवंबर को इस न्यायालय में कामकाज का दिन (सिटिंग डे) घोषित किया गया है। वहीं, दूसरे शनिवार, 12 दिसंबर 2026 को इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज का दिन घोषित किया गया है।' नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'सोमवार, 16 नवंबर के लिए निर्धारित मामलों की सुनवाई मंगलवार, 17 नवंबर को की जाएगी। यह सुनवाई उस तारीख के लिए पहले से तय मामलों के अतिरिक्त होगी। इसके पहले दिल्ली सरकार ने प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

इस दिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और स्वायत्त निकायों (ऑटोनॉमस बॉडीज) के परिसर बंद रहेंगे। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, 'प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर 16 नवंबर को पूरी दिल्ली में सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के कार्यालयों में भी अगले सोमवार को छठ की छुट्टी रहेगी। पिछले साल, दिल्ली में छठ घाटों की कुल संख्या 1,326 थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से शुरू होने वाले चार दिवसीय छठ पर्व की तैयारियों की देखरेख के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। छठ समिति को घाटों और आयोजन स्थलों पर एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र), पीने के पानी, चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन सुरक्षा, मोबाइल शौचालय, सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई, फॉगिंग (कीटनाशक छिड़काव) और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

## छठ पूजा पर दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा : 16 नवंबर को बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, यमुना घाटों पर तैयारियां तेज

नई दिल्ली (एजेंसी)



लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने छठ पूजा के मुख्य दिवस पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 को राजधानी में सार्वजनिक अवकाश (पब्लिक हॉलिडे) घोषित किया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकारी दफ्तर, उपक्रम और स्वायत्त संस्थान रहेंगे बंद अधिसूचना के मुख्य बिंदुः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, प्रतिहार षष्ठी (सूर्य षष्ठी/छठ पूजा) के अवसर पर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी प्रशासनिक कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। संस्थानों का दायराः इस आदेश के तहत दिल्ली सरकार के सभी सचिवालयी व क्षेत्रीय दफ्तरों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और अपने नियमों के तहत संचालित होने वाले स्वायत्तशासी संस्थानों में सार्वजनिक छुट्टी प्रभावी रहेगी। घाटों का निर्माण व सफाईः पूर्वांचल समाज के इस सबसे बड़े आस्था के पर्व को लेकर दिल्ली भर में, विशेषकर यमुना के प्रमुख घाटों और कृत्रिम पोखरों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रकाश, पेयजल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हवा की गुणवत्ता 'खराब': पर्व के उत्साह के बीच दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है।

## फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, एक भारतीय नाविक घायल : केंद्रीय मंत्री सोनोवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)



फारस की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले तेल-टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक के घायल होने की सूचना है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। सोनोवाल ने 'एक्स' पोस्ट में बताया कि 'एमची फुजैराह एनर्जी' नाम का यह जहाज अल-रुवाइस से दुबई जा रहा था, तभी इस पर किसी वस्तु (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 10 नवंबर को, लाइबेरिया के झंडे वाले वीएलसीसी 'एमटी फुजैराह एनर्जी' शिप जिसमें 6 भारतीय नाविक सवार थे, फारस की खाड़ी से अल-रुवाइस से दुबई जाते समय किसी वस्तु से हमला हुआ। इस हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उसे मामूली चोट आई है और आगे की मेडिकल जांच के लिए सुरक्षित रूप से किनारे पर ले आया गया है। सोनोवाल ने आगे कहा कि बाकी 18 क्रू सदस्य, जिनमें 5 अन्य भारतीय नाविक भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं। मंत्री ने कहा, बाकी 18 क्रू सदस्य, जिनमें 5 अन्य भारतीय नाविक भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं और उनके बारे में जानकारी मिल गई है।

हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल और भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में कमर्शियल शिपिंग और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हाल (3 नवंबर) ही में विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत के 23 नागरिकों ने जान गंवाई है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि काला सागर (ब्लैक सी) क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में पांच भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य अभी भी लापता हैं।

## सोनिया, खड़गे और इमरान मसूद के बयान कांग्रेस की एंटी-इंडिया और एंटी-हिंदू' सोच के प्रमाण : भाजपा

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दीपावली पर कांग्रेस नेताओं के बयानों और अयोध्या के विवादित ढांचे को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की सुव्यवस्थित 'एंटी-इंडिया' और 'एंटी-हिंदू' सोच का जीता-जागता प्रमाण है।

सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी अभी दीपावली का पर्व गुजरा है और आज भ्रातृ द्वितीया है। जहां देश विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ राजनीति नई निम्नताओं की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है।' उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'डेड इकॉनोमी' वाले बयान पर जिक्र करते हुए कहा, भारत की तथाकथित 'डेड इकॉनोमी' में, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था, सिर्फ धनतेरस के दिन पूरा यूरोप 3 महीने में जितना सोना-चांदी खरीदता है, उतना इस तथाकथित 'डेड इकॉनोमी' ने एक दिन में खरीदकर दिखाया था। इसके बावजूद यह दर्शाता है कि भारत की परंपराओं, धर्म और संस्कृति के प्रति कितनी अवमानना और घृणा विपक्ष के नेताओं में भरी हुई है। भाजपा सांसद ने कहा, 'यह सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़े ने इसे खुशियों की ईद बना दिया। आश्चर्य की बात है। वो जिस राज्य से आते हैं, कर्नाटक में त्योहार के लिए उत्सव शब्द का प्रयोग होता है।

यह 'ईद' शब्द कहां से आ गया? यह दर्शाता है कि एक बार फिर भारतीय धर्म और संस्कृति को किस सीमा तक जाकर अपमानित किया जा सकता है, यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के आचरण में दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा, यह भी आश्चर्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं देने में समस्या नहीं है, मलेशिया के राष्ट्रपति भी दीपावली की शुभकामनाएं दीपावली ही कहकर दे रहे हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी दिवाली लिखा हुआ है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह पर 'खुशियों की ईद' छपा हुआ है। दीपावली को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया।

उन्होंने कहा, 'कांग्रेस सांसद ने दीपावली को 'मानव जनित रोग' कहा है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले 'इंडी' गठबंधन के लोग तमिलनाडु में हिंदू धर्म को 'बैक्टीरिया', 'एचआईवी' और 'वायरस' बोल चुके हैं। अब इमरान मसूद 'मानव जनित रोग' बता रहे हैं। साथ ही, सुधांशु त्रिवेदी ने सोनिया गांधी के 'बाबरी मस्जिद' वाले बयान पर जवाब दिया।

## आसमान में वायुसेना के सारंग का प्रदर्शन, पांच हेलीकॉप्टरों के साथ दिखेंगे वायुसेना के जांबाज

नई दिल्ली (एजेंसी)



**सारंग के रंग-बिरंगे हेलीकॉप्टर भी इसकी खास पहचान हैं। टीम का नाम मोर से प्रेरित है। मोर की सुंदरता और आकर्षक रंगों को दर्शाते ये हेलीकॉप्टर जब एक साथ आसमान में उड़ान भरते हैं, तो अपनी अलग छाप छोड़ते हैं**

भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम गुजरात के वडोदरा में अपने शानदार हवाई करतबों से दर्शकों को रोमांचित करने जा रही है। 12 से 15 नवंबर तक होने वाला यह विशेष प्रदर्शन वायुसेना की 11वीं स्क्वाड्रन की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सारंग के रंग-बिरंगे हेलीकॉप्टर भी इसकी खास पहचान हैं। टीम का नाम मोर से प्रेरित है।

मोर की सुंदरता और आकर्षक रंगों को दर्शाते ये हेलीकॉप्टर जब एक साथ आसमान में उड़ान भरते हैं, तो अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। अपनी शुरुआत से ही सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने देश और विदेश के कई प्रतिष्ठित हवाई प्रदर्शनों में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व किया है। अपने शानदार प्रदर्शन से इसने दुनियाभर के दर्शकों को आकर्षित किया है। इसके करतब भारतीय पायलटों की दक्षता के साथ-साथ देश में विकसित विमानन तकनीक की बढ़ती क्षमता को भी प्रदर्शित करते हैं।

वडोदरा में होने वाला यह प्रदर्शन खास तौर पर युवाओं और स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्लैटिनम जुबली समारोह का हिस्सा है। इस दौरान सारंग टीम के पांच हेलीकॉप्टर एक साथ आसमान में उड़ान भरेंगे और अपने असाधारण कौशल, सटीक नियंत्रण तथा बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करेंगे। सारंग भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर हवाई करतब प्रदर्शन टीम है। इसे पांच हेलीकॉप्टरों के साथ प्रदर्शन करने वाली अपनी तरह की अनूठी सैन्य टीम होने का गौरव प्राप्त है। यह टीम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर 'ध्रुव' के जरिए अपने करतब दिखाती है। सारंग के प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत पांच हेलीकॉप्टरों का बेहद करीब रहकर एक साथ उड़ान भरना है। हवा में इस तरह का तालमेल बनाए रखने के लिए पायलटों को असाधारण कौशल, अनुशासन और सटीक नियंत्रण की जरूरत होती है।

एक साथ उड़ते हेलीकॉप्टर जब अलग-अलग आकृतियां बनाते हुए आसमान में करतब दिखाते हैं, तो यह नजारा दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पांच हेलीकॉप्टरों को आसमान में अद्भुत तालमेल के साथ उड़ते देख विद्यार्थियों में विमानन, विज्ञान और तकनीक के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही उन्हें सशस्त्र बलों में करियर बनाने और देश की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। दरअसल इस तरह के हवाई प्रदर्शन युवाओं, खासकर स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी खास महत्व रखते हैं।

## दिल्ली में 14 लाख की संदिग्ध दवाएं जब्त, 62 में से 37 दुकानों की जांच में गड़बड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली में दवाओं की बिक्री और भंडारण के नियमों की बड़े पैमाने पर अनदेखी हो रही है। मादीपुर गांव में बिना लाइसेंस एक आवासीय परिसर में रखी करीब 14 लाख रुपये की संदिग्ध दवाएं औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साथ मिलकर जब्त की हैं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं, एंटीबायोटिक दवाओं की अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 62 दवा प्रतिष्ठानों की जांच की गई तो 37 में नियमों का उल्लंघन मिला। यानी करीब 60 फीसदी प्रतिष्ठानों पर गड़बड़ी सामने आई है। औषधि नियंत्रण विभाग और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चार और पांच नवंबर को मादीपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई की। यहां एक आवासीय परिसर में बिना जरूरी लाइसेंस के दवाओं का भंडारण किया गया था। इन दवाओं को बिक्री और वितरण के लिए रखा गया था।

विभाग को दवाओं की गुणवत्ता भी संदिग्ध लगी है। औषधि निरीक्षक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दवाओं को जब्त कर उनके नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। विभाग अब जब्त दवाओं की अभिरक्षा और आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं की मनमानी बिक्री पर रोक लगाने के लिए विभाग ने कृष्णा नगर, जीटीबी नगर (किंग्सवे कैंप) और रोहिणी में 41 दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इनमें 25 पर नियमों का उल्लंघन मिला। प्रमुख गड़बड़ियों में पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी के बिना दवाओं की बिक्री, दवाओं की खरीद-बिक्री का सही रिकॉर्ड नहीं रखना और डॉक्टर की वैध पर्ची के बिना ऐसी दवाएं देना शामिल है। जांच का दायरा एम्स और सफदरजंग अस्पताल के आसपास की दवा दुकानों तक भी पहुंचा। यहां 21 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 12 में नियमों का उल्लंघन मिला। विभाग ने अलग-अलग स्थानों से कुल 110 दवाओं के नमूने भी गुणवत्ता जांच के लिए एकत्र किए हैं।

## सरकार ने संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियामक ढांचा प्रस्तावित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)



केंद्र सरकार ने बुधवार को संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के पात्र पेशेवरों के लिए अनंतिम पंजीकरण (प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन) हेतु एक व्यापक नियामक ढांचे का प्रस्ताव रखा। इस ढांचे में कौशल उन्नयन, योग्यता के आकलन तथा नियमित पंजीकरण प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्रावधान किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत 'नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स' (एनसीएएचपी) द्वारा प्रस्तावित इस ढांचे का उद्देश्य पेशेवर पंजीकरण में अधिक एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। साथ ही, यह योग्य पेशेवरों को निर्धारित मानकों के अनुसार अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित अवसर भी प्रदान करता है। इन प्रस्तावित नियमों की एक मुख्य विशेषता योग्य संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अनंतिम पंजीकरण के लिए एक पारदर्शी और मानकीकृत प्रणाली बनाना है, जो एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप हो। इस ढांचे में पात्रता मानदंड, दस्तावेजों का सत्यापन और पंजीकरण की स्पष्ट प्रक्रियाएं शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेशेवर मान्यता कानूनी आवश्यकताओं और योग्यता मानकों के अनुरूप हो। गौरतलब है कि इन प्रस्तावित नियमों में अनंतिम रूप से पंजीकृत पेशेवरों के लिए नियमित पंजीकरण की शर्तें पूरी करने के अवसर भी दिए गए हैं। इसके तहत वे कौशल बढ़ाने के लिए निर्धारित 'ब्रिज कोर्स', पर्यवेक्षित क्लिनिकल प्रशिक्षण और (जहां लागू हो) न्यूनतम योग्यता परीक्षाएं पूरी कर सकते हैं।

**इस ढांचे में कौशल उन्नयन, योग्यता के आकलन तथा नियमित पंजीकरण प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्रावधान किए गए हैं**

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, योग्यता-आधारित यह दृष्टिकोण निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देने, करियर में आगे बढ़ने में मदद करने और संबद्ध तथा स्वास्थ्य सेवाओं (अलाइड एंड हेल्थकेयर सर्विसेज) की गुणवत्ता को मजबूत करने का प्रयास करता है। प्रस्तावित ढांचा कौशल विकास, पेशेवर योग्यता और नियामक जवाबदेही पर भी जोर देता है। एनसीएएचपी ने 'अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रेगुलेशंस, 2026 के ड्राफ्ट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन' (अस्थायी पंजीकरण के मसौदे) पर 4 दिसंबर तक आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इन प्रस्तावित नियमों में एक एकीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की परिकल्पना की गई है, ताकि आवेदन जमा करने, दस्तावेजों के सत्यापन, पात्रता के आकलन और अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। पात्र पेशेवरों को अस्थायी पंजीकरण मिलने पर एक 'प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर' (पीआर यूआईडी) दिया जाएगा, जिससे उनकी व्यवस्थित पहचान और नियामक निगरानी संभव हो सकेगी।

## सम्पादकीय



# रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा

भारत की आर्थिक प्रगति का आधार केवल बड़े उद्योग और निवेश नहीं, बल्कि छोटे कारोबार, नए उद्यम और स्वरोजगार के अवसर भी हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत बनती है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

भारत में लंबे समय से उद्यमिता के क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा रही है। विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं के सामने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करना आसान नहीं होता। कई बार प्रतिभा, अनुभव और व्यवसाय का विचार होने के बावजूद पर्याप्त पूंजी के अभाव में लोग अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। स्टैंड-अप इंडिया योजना इसी समस्या को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी।

इसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमी और एक महिला उद्यमी को नया उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का ऋण ग्रीनफील्ड यानी पहली बार स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के लिए दिया जाता है। यह ऋण विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना का महत्व केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य ऐसे लोगों को उद्यमी बनाना है, जो अब तक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण कारोबार की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। जब किसी महिला को अपना उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलता है या अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू करता है, तो उसका लाभ केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से भी यह योजना महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, व्यापार और उद्योग सहित हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं।

इसके बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने और व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। बैंक ऋण और संस्थागत सहायता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

# बढ़ती विकास दर, घटती खुशहाली

**सत्यपाल वशिष्ठ**

वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की विकास दर का ऊंचा बने रहना निश्चित रूप से उत्साहजनक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर को भी 6.6 प्रतिशत से संशोधित करके 7 प्रतिशत कर दिया है। ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और विकास की संभावनाओं को दर्शाते हैं। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की 'गरीबी एवं समानता रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुपात वर्ष 2011 में 27.1 प्रतिशत था, जो वर्ष 2023 में घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गया है।

यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रिपोर्ट में बढ़ती खपत, रोजगार के अवसरों और खाद्य सब्सिडी सहित विस्तारित सामाजिक कल्याण योजनाओं के योगदान को भी स्वीकार किया गया है। लेकिन वर्तमान में स्थायी रोजगार के अभाव और महंगाई से त्रस्त जनता को देखते हुए इन उत्साहजनक आंकड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो आम नागरिक का जीवन आर्थिक रूप से आसान होने के बजाय कठिन क्यों होता जा रहा है? विकास दर में वृद्धि और आम आदमी की आर्थिक खुशहाली के बीच दिखाई देने वाला यह अंतर गंभीर विचार-विमर्श की मांग करता है।

इन उपलब्धियों के उत्साह में उन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जो आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। वर्ष 2026 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 122 देशों में भारत का 100वां स्थान इस बात की याद दिलाता है कि आर्थिक विकास अपने आप पर्याप्त पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी नहीं देता। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी लगातार बनी हुई आर्थिक असमानताओं की ओर संकेत करती है। मजदूरी में असमानता अब भी बनी हुई है। सरकारी नौकरियों के लिए लंबी कतारें देश में रोजगार की स्थिति को दर्शाती हैं। नियमित वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और अपेक्षाकृत स्थायी रोजगार की संभावना युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित करती है। युवाओं की परेशानी केवल नौकरी न मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके माता-पिता ने जीवनभर की बचत उनकी शिक्षा पर खर्च की होती है। इसके बावजूद जब उन्हें योग्यता के अनुरूप सुरक्षित रोजगार नहीं मिलता तो परिवारों में निराशा बढ़ती है। जीडीपी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में वृद्धि को मापती है, लेकिन यह नहीं बताती कि इस अतिरिक्त आय का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किस प्रकार हुआ है।

यह भी जरूरी नहीं कि उत्पादन बढ़ने के अनुपात में रोजगार के अवसर बढ़ें। पूंजी प्रधान उद्योगों और तकनीक आधारित गतिविधियों से उत्पादन तथा कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ता है, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन अपेक्षाकृत कम होता है। यदि कंपनियों के मुनाफे में तेजी से वृद्धि हो और कर्मचारियों के वेतन में अपेक्षित सुधार न हो तो आर्थिक विकास का लाभ सीमित वर्ग तक सिमटकर रह जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में महंगाई आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अक्टूबर 2026 के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से घरेलू बजट प्रभावित होता है। महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग पर पड़ता है।

## प्रेरणादायक विचार



आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा चल रहा है। लोकतंत्र असली लोकतंत्र में नहीं है कि हम सामने वाले को मुजरिम ठहरा दे अस्थि लोकतंत्र वह है जब व्यक्ति अपने अधिकार को सुने समझ कर उनकी रक्षा करता है, और उन अधिकारों के लिए सामने वाले को चुनौती भी दे। लेकिन आजकल का लोकतंत्र कुछ और भी बयां कर रहा है।

करिश्मा गुज्जर (खारी)

# प्रतिबंध नहीं, सुरक्षित डिजिटल संसार की जरूरत

**डॉ. प्रियंका सौरभ**

इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट केवल मनोरंजन या संवाद का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा, सूचना, अभिव्यक्ति और सामाजिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। विशेषकर बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया ज्ञान के नए द्वार खोलती है। ऐसे समय में बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह वंचित करना उनके विकास के अवसरों को सीमित करने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार से जुड़े अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के नाम पर व्यापक और एकमुश्त प्रतिबंध उचित समाधान नहीं हो सकते। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या में डिजिटल पहुँच का महत्व भी सामने आता है। हालांकि, इस अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इंटरनेट की खुली छूट दे दी जाए। बच्चों के शैक्षणिक विकास में इंटरनेट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन कक्षाएँ, शैक्षणिक वीडियो, आभासी प्रयोगशालाएँ और विभिन्न शिक्षण मंच पारंपरिक शिक्षा के पूरक बन चुके हैं। केंद्र सरकार के दीक्षा मंच और पीएम ई-विद्या जैसी पहल ने डिजिटल शिक्षा को व्यापक बनाने में योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए इंटरनेट गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुँच का माध्यम बन सकता है। जिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय या अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ डिजिटल माध्यम शिक्षा की कमियों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं।

इंटरनेट बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन को भी प्रोत्साहित करता है। वे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, पर्यावरण, कला और तकनीक जैसे विषयों पर अपनी रुचि के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कविताएँ, कहानियाँ, चित्र और विचार साझा कर सकते हैं। इससे उनमें अभिव्यक्ति का आत्मविश्वास और संवाद की क्षमता विकसित होती है। सूचना का अधिकार भी इंटरनेट के माध्यम से अधिक प्रभावी बनता है। बच्चे अपने आसपास की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को समझकर जागरूक नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।



डिजिटल पहुँच समावेशी शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लिए स्क्रीन रीडर, ऑडियो पुस्तकें, सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री और अन्य सहायक तकनीकें शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती हैं।

दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी देश-दुनिया के शैक्षणिक संसाधनों से जुड़ने का अवसर मिलता है। इंटरनेट डिजिटल साक्षरता विकसित करता है, जो भविष्य के रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल बन चुकी है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शोध, डिजिटल संचार और तकनीकी नवाचार के दौर में बच्चों को डिजिटल दुनिया से दूर रखना उनके भविष्य की संभावनाओं को कमजोर कर सकता है।

हालाँकि, इंटरनेट के लाभों के साथ गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज अभिभावकों, शिक्षकों, सरकार और डिजिटल मंचों के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन यौन शोषण, बच्चों को बहला-फुसलाकर अनुचित गतिविधियों में शामिल करना, साइबर बुलिंग, अश्लील सामग्री, फर्जी पहचान और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी घटनाएँ बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कई बार बच्चे अनजान व्यक्तियों से संपर्क में आ जाते हैं और अपनी निजी जानकारी, तस्वीरें या स्थान संबंधी विवरण साझा कर देते हैं। इसका दुरुपयोग उनके मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। साइबर बुलिंग भी एक गंभीर समस्या है। सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियाँ, धमकियाँ, मजाक उड़ाना और निजी तस्वीरों का दुरुपयोग बच्चों के आत्मविश्वास तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मंचों द्वारा बच्चों के व्यवहार, पसंद और व्यक्तिगत जानकारी का अत्यधिक संग्रह उनकी निजता के अधिकार के लिए चुनौती है। एल्गोरिदम आधारित सामग्री बच्चों को लगातार स्क्रीन पर बनाए रखने का प्रयास करती है, जिससे उनकी पढ़ाई, नींद, शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए समाधान इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में नहीं, बल्कि सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण तैयार करने में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का मूल संदेश भी यही है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले उपाय तर्कसंगत, आनुपातिक और उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। किसी विशेष खतरे के समाधान के नाम पर सभी बच्चों की इंटरनेट पहुँच समाप्त कर देना उचित नहीं है। प्रतिबंधों के बजाय जोखिम के अनुसार सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

सबसे पहले, डिजिटल मंचों को बच्चों के अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। बच्चों के खातों में निजता संबंधी व्यवस्थाएँ पहले से सुरक्षित होनी चाहिए। अनजान व्यक्तियों के संदेशों, अनुचित संपर्कों और संवेदनशील सामग्री तक पहुँच को सीमित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के व्यक्तिगत आँकड़ों का अनावश्यक संग्रह और व्यावसायिक उपयोग रोका जाना चाहिए। आयु के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने और हानिकारक सामग्री की पहचान करने के लिए प्रभावी तकनीकी व्यवस्थाएँ विकसित करनी चाहिए।

दूसरा, अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों पर केवल निगरानी रखने के बजाय उनके साथ विश्वास और संवाद का संबंध विकसित करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि इंटरनेट पर प्रत्येक व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता और निजी जानकारी साझा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। अभिभावकीय सहमति, आयु के अनुरूप नियंत्रण और समय-समय पर संवाद के माध्यम से बच्चों को जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार सिखाया जा सकता है। बच्चों की निजता और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए मार्गदर्शन देना आवश्यक है। तीसरा, डिजिटल सुरक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) के माध्यम से साइबर सुरक्षा, डिजिटल शिष्टाचार, ऑनलाइन धोखाधड़ी, निजता और सूचना की सत्यता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

# विदेशी सोशल मीडिया पर अंकुश है जरूरी

**डा. अश्विनी महाजन**

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई देशों में सत्ता परिवर्तन देखे हैं, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल प्रमुख हैं। इन देशों में हुए सत्ता परिवर्तनों में एक बात समान थी- सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए और हवा मिली। इन देशों में नागरिकों को उद्वेलित करने मे सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया। श्रीलंका में, इन विरोध-प्रदर्शनों के कारण अंततः राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश में, चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।

नेपाल का 'जेन-जी' आंदोलन भी इससे कुछ अलग नहीं था। वहां भी, सोशल मीडिया ने खराब शासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाबदेही और बेरोजगारी से जुड़ी चर्चाओं को बढ़ावा दिया। नेपाल में, युवा प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने और सूचनाएं फैलाने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही इसका इस्तेमाल आधिकारिक बयानों को चुनौती देने के लिए भी किया गया। यह आंदोलन सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के साथ समाप्त हुआ। एक बड़ी चिंता यह है कि जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी तकनीक का इस्तेमाल सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए करते हैं, वहीं इन प्लेटफॉर्म्स की खुद की जवाबदेही तय करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यहां तक कि जब इन प्लेटफॉर्म्स का गलत आचरण सामने आता है, तब भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करना संभव नहीं होता। भारत सरकार के पास इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाईडलाईंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियमावली 2021 के अंतर्गत नियम 4 (2) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) और यौन अपराधों या बच्चों के यौन शोषण से संबद्ध कुछ संगीन अपराधों के संदर्भ में यह अधिकार है कि संदेश के प्रारंभ कर्ता की पहचान कर सके और अपराधियों को दंड दे सके।

नियम में यह भी प्रावधान है कि ऐसा तब किया जाएगा जब कम सख्त तरीके प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाएं। गौरतलब है कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफार्म निजता के नाम पर नियमों को भी मानने से इंकार करते हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया कंपनी 'मेटा' के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने बयान दिया था, कि यदि उन्हें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समाप्त करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो वह भारत से निकल जाएंगे, यानी इन सोशल मीडिया सेवाओं को भारत में समाप्त कर देंगे। उनके इस बयान से यह समझा जा सकता है कि भारत सरकार उन्हें कुछ हिदायत दे रही है, जिनका वे पालन नहीं करना चाहते और इसलिए अपने इस बयान से जनता में राय बनाते हुए भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो उन पर अंकुश न लगाए।

क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और क्या हैं भारतीय नियम? : मेटा का कहना है कि व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्टिड, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुप्त होते हैं, यानी सिर्फ वही व्यक्ति जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं, वही आपके मैसेज पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी वॉइस कॉल और वीडियो कॉल भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टिड होती है। अब जब भारत सरकार संगीन अपराधों के लिए व्हाट्सएप से जानकारी मांगती है तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन यानी निजता का हवाला देकर, व्हाट्सएप उससे बचना चाहता है।

दूध की धुली नहीं है मेटा : एक ओर जहां मेटा कंपनी ऊंचे आदर्शों का दंभ भरते हुए भारत सरकार के नियमों को मानने से यह कहकर इंकार कर रही है कि इससे उसकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन समाप्त हो जाएगी और यह उनकी वैश्विक स्तर वैशिष्ट्य है, जिसके लिए व्हाट्सएप दुनिया में जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर यह कंपनी यूजर्स का डाटा बिना उनकी अनुमति के अन्य लोगों को कीमत के बदले उपलब्ध कराती रहती है। यूजर्स डाटा को बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कंपनी ने अपनी प्राइवेसी नीति में भी बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ मेटा ने स्वयं को अधिकृत किया कि वो अन्य मेटा कंपनियों के साथ उनका डेटा साझा कर सकती है। 2021 में किए गए बदलाव में यह प्रावधान था कि जो ग्राहक ऐसा नहीं चाहते, वे उनकी सेवा छोड़ सकते हैं। मेटा का यह भी कहना था कि इससे उसकी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। बाद में भारत की नियामक संस्था कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने कहा कि यह बदलाव कि यदि उन्हें डाटा साझा करना स्वीकार नहीं तो वे मेटा सेवा छोड़ सकते हैं, अनुचित है।

आयोग ने कहा कि यह डेटा साझा करना व्हाट्सएप सेवाओं के उपलब्ध कराने से संबद्ध नहीं है और उसने मेटा पर 213 करोड रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया और उसके बदलाव को रोक कर उपभोक्ताओं के चयन के अधिकार को बहाल किया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मेटा कंपनी ने ग्राहकों की निजी जानकारियों का अनुचित उपयोग किया। कैंब्रिज एनालेटिका घोटाले में फेसबुक के लाखों यूजर्स का डाटा किसी तीसरी एप के माध्यम से लेकर उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। इन लाखों यूजर्स ने अपने इस डाटा का उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं दी थी। 2019 में अमरीका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने निजता हनन के लिए फेसबुक पर 5 अरब डालर का जुर्माना लगाया। 2021 में फ्रांसिस हॉगन ने इंस्टाग्राम के आंतरिक दस्तावेजों का खुलासा करते हुए इंस्टाग्राम के किशोरों के मानसिक और अन्य प्रकार से स्वास्थ्य पर पडने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया और यह साबित किया कि मेटा कंपनी का इस बाबत रुख गैर-जिम्मेदाराना रहा। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट फाइंडिंग मिशन द्वारा यह बताया गया कि फेसबुक सामाजिक घृणा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। बे-रोकटोक सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की घृणा फैलने के कितने दुष्परिणाम होते हैं, यह उसका उदाहरण है। म्यांमार में फेसबुक पर सोशल मीडिया पोस्टों ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा का वातावरण तैयार किया।

मेटा द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिग्रहण और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के कारण अलग-अलग देशों में सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो गई है। खास तौर पर फेसबुक द्वारा इंस्टाग्राम और व्हाटसएप के अधिग्रहण के बाद सोशल मीडिया में मेटा का एकछत्र राज्य स्थापित हो चुका है। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि मेटा कंपनी यूजर डाटा को ट्रेक करते हुए लक्षित विज्ञापन भी करती है। व्हाटसएप के माध्यम से मेटा कंपनी गलत जानकारियां प्रसारित करने का काम करती है और ऐसा देखा गया है कि व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों की वजह से दंगे, उत्पीडन की गतिविधियां तो होती ही हैं।

# उत्तर प्रदेश 2027 : सत्ता की परीक्षा, समीकरणों की अग्निपरीक्षा

**ललित गर्ग**

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला निर्णायक राजनीतिक रणक्षेत्र है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता, भाजपा संगठन में बदलाव, अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति, विपक्षी दलों के संभावित गठजोड़ और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बन रहे नए समीकरण-सभी पर देश की निगाहें टिकी हैं। प्रश्न है कि योगी की मजबूत पकड़ के सामने विपक्ष की चुनौती, मुस्लिम मतों से आगे हिंदू मतदाताओं की बदलती मनोदशा निर्णायक बन पायेगी? प्रश्न यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चेहरा एवं योजनाएं भी क्या प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व एवं भाग्य रचने में सहायक होगी?

सबसे पहले भाजपा की स्थिति को देखें तो उसके सामने सबसे बड़ी ताकत योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों का दावा है। कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेस-वे, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास तथा केंद्र-राज्य की योजनाओं को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। योगी का दावा है कि 2027 का मुकाबला '80 बनाम 20' के रूप में होगा और भाजपा गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। लेकिन चुनावी राजनीति में दावे और वास्तविक जनभावना के बीच अंतर होता है। इसलिए भाजपा के लिए चुनौती केवल अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सत्ता-विरोधी भावना उसके पारंपरिक सामाजिक आधार में सेंध न लगाए।

भाजपा की रणनीति में इस बार मुस्लिम समाज के भीतर पहुंच बनाने का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगस्त 2026 में पार्टी की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के दो मुस्लिम नेताओं-पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे 2027 से पहले भाजपा की पसमांदा तथा मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति से जोड़ा है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26 प्रतिशत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में उनका चुनावी प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। लेकिन भाजपा के लिए चुनौती यह है कि मुस्लिम मतों में सेंध लगाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन अपने हिंदू सामाजिक आधार को एकजुट बनाए रखना हो सकता है। यहीं चुनाव का दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की चर्चा के साथ हिंदू मतदाताओं के भीतर बदलती प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। मतदाता केवल जाति और धर्म के आधार पर मतदान नहीं करता। रोजगार, महंगाई, किसान, शिक्षा, युवाओं के अवसर, स्थानीय विधायक की छवि, प्रशासनिक व्यवहार और विकास की वास्तविक पहुंच भी चुनावी निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए 2027 का चुनाव केवल '80 बनाम 20' के राजनीतिक आख्यान से समझना शायद पर्याप्त नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर यही है।

अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक समीकरणों को विधानसभा स्तर तक मजबूत करना चाहेंगे। पीडीए-पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला भाजपा के गैर-यादव पिछड़े और दलित मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। सपा के सामने चुनौती यह है कि वह अपने सामाजिक समीकरण को केवल चुनावी नारा न रहने दे, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन के माध्यम से उसे वास्तविक राजनीतिक शक्ति में बदल सके। बसपा की भूमिका को भी नजरअंदाज करना भाजपा और सपा दोनों के लिए जोखिम भरा होगा। यदि मायावती दलित मतदाताओं के अपने पुराने आधार को पर्याप्त रूप से सक्रिय कर पाती हैं, तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला परिणाम बदल सकता है। कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है, लेकिन यदि वह सपा के साथ तालमेल बनाकर लड़ती है तो विपक्षी मतों के बिखराव को कुछ हद तक रोक सकती है। लेकिन यहां पूर्व के अनुभवों के आधार पर सपा कांग्रेस से तालमेल करने से पहले फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है।

भाजपा के सामने दूसरी चुनौती अपने गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को संतुलित रखने की है। निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) तथा अन्य सहयोगी दलों की अपेक्षाएं, टिकट वितरण और क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं चुनाव के समय महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भाजपा का मजबूत संगठन इन मतभेदों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन टिकट वितरण में छोटी-सी चूक भी कुछ क्षेत्रों में बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। अमित शाह की सक्रियता भी इस चुनाव की गंभीरता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति केवल लखनऊ से नहीं, बल्कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में तैयार होने की संभावना है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता और प्रशासनिक छवि भाजपा के लिए सबसे बड़ा स्थानीय चुनावी चेहरा है। इसलिए वास्तविक चुनौती यह होगी कि योगी का नेतृत्व और केंद्रीय संगठनात्मक रणनीति कितनी प्रभावी तरह से एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चुनता है-स्थिरता और निरंतरता या परिवर्तन की आकांक्षा। भाजपा के पास संगठन, सत्ता, योगी का चेहरा और व्यापक चुनावी मशीनरी है। विपक्ष के पास सत्ता-विरोधी भावना, सामाजिक न्याय का मुद्दा और भाजपा के खिलाफ विभिन्न वर्गों को एकजुट करने की संभावना है। इसलिए अभी किसी एक दल की जीत को निश्चित मानना जल्दबाजी होगी। भाजपा के लिए 300 पार का लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन उसे कमजोर समझना भी विपक्ष की भूल होगी। सपा के सामने अवसर बड़ा है, लेकिन उसे अवसर को जीत में बदलने के लिए सामाजिक समीकरण के साथ संगठनात्मक मजबूती भी दिखानी होगी। बसपा और कांग्रेस की भूमिका कई सीटों पर 'गेम चेंजर' बन सकती है।

योगी आदित्यनाथ के सामने 2027 का चुनाव केवल विपक्षी दलों के बनते-बिगड़ते समीकरणों, मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण और समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव की चुनौती नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

# यूपी : पराली प्रबंधन पहल से किसानों को मिला नया रास्ता, खेतों का अवशेष बना कमाई का साधन

लखनऊ (एजेंसी)



**प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं। बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के योगेश इसका उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले एक फसल की कटाई के बाद खेतों में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी**

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पराली प्रबंधन को किसानों के लिए आर्थिक अवसर में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने पर है। इसके तहत पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आय, खेतों को जैविक खाद और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत देने की पहल की जा रही है।

इस व्यवस्था से पराली अब किसानों के लिए समस्या नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया बन रही है। प्रदेश में अभी 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने हैं। बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के योगेश इसका उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले एक फसल की कटाई के बाद खेतों में बची पराली उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती थी। उसे जलाने पर जुर्माने का डर और खेत में छोड़ने पर अगली फसल की बुआई में देरी की आशंका रहती थी। लेकिन अब फसल कटते ही पराली खेत से उठ जाती है और वह समय से अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं।

टिकरा गांव के किसान बलराम बताते हैं कि पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से उसके निस्तारण पर होने वाला खर्च बच रहा है।

पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। कई बार समय पर खेत खाली करने के दबाव में किसान पराली जलाने को मजबूर हो जाते थे। इससे पर्यावरण के साथ मिट्टी की सेहत और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को भी नुकसान पहुंचता था। अब पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में हो रहा है और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। योगेश और बलराम जैसे किसानों के अनुभव बताते हैं कि पराली प्रबंधन की नई व्यवस्था ग्रामीण खेती की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में फसल अवशेषों के उपयोग को लेकर विकसित की जा रही व्यवस्था किसानों को पराली जलाने से रोकने के साथ ही कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के बीच एक नया आर्थिक संबंध स्थापित कर रही है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का यह मॉडल विकसित किया है। बेहतर व्यावसायिक चक्र तैयार करने के लिए सप्लाई चेन से जुड़े सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को विशेष रूप से जोड़ा गया और उन्हें पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए तैयार किया गया। इस मॉडल का उद्देश्य खेतों से पराली का समयबद्ध संग्रहण, उसका सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिल रही है और फसल अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए हो रहा है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके अलावा आग की तेज गर्मी मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित होती है। इसके विपरीत पराली का उचित प्रबंधन और जैविक अपघटन मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है।

इससे मिट्टी की संरचना, नमी बनाए रखने की क्षमता और पोषक तत्वों के चक्र को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करने से भी मिट्टी की सेहत सुधारने की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

## यूपी चुनाव के लिए सामने आया नया गठबंधन, 2027 में मिलकर लड़ेंगे ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद

लखनऊ (एजेंसी)



यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए गठबंधन किया है। बताया जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा कल लखनऊ में की जाएगी। गठबंधन की योजना प्रदेश की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। यूपी का चुनाव अभी तक भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है पर औवैसी-चंद्रशेखर के दलों के गठबंधन के एलान के बाद राज्य में नये राजनीतिक समीकरण पैदा हो सकते हैं। इस नए मोर्चे में कुछ अन्य छोटे दल भी शामिल हो सकते हैं।

इसके पहले, ओवैसी ने यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी जिस पर अखिलेश यादव ने इन्कार कर दिया था। इस गठबंधन के जरिये प्रदेश के दलितों और मुस्लिमों के 40 फीसदी वोटबैंक को एकजुट करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ओवैसी ने चुनाव को लेकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसका एलान बुधवार को लखनऊ में होगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं। वह प्रदेश में दलितों के बीच लगातार अपनी पैठ मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने का फायदा समाजवादी पार्टी भी उठाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य छोटे दलों का गठबंधन प्रदेश में नए समीकरण पैदा करने के साथ ही इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।

## नीतीश पर कांग्रेस की टिप्पणी के बाद झा का पलटवार, बोले- ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए



पटना (एजेंसी)

जनता दल यूनाईटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का 50 साल का सार्वजनिक जीवन रहा है।

कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के दौरान वह दो साल जेल में भी रहे थे। इसके बावजूद उनके बारे में इस तरह की ओछी और हल्की टिप्पणी करना दुखद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। संजय झा ने कहा कि बिहार में आज जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वह नीतीश कुमार की देन है।

**विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका**

संजय झा ने विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह अलग-अलग दलों के नेताओं से मिल रहे थे, तब कई नेताओं ने कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखकर मोर्चा बनाने की सलाह दी थी। हालांकि, कुछ नेता कांग्रेस को साथ रखने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में कथित तौर पर कहा था कि 2024 में नीतीश कुमार को रोकना चाहिए था, तभी यह परिस्थिति नहीं बनती।

**विपक्षी गठबंधन की नींव नीतीश कुमार के प्रयासों से तैयार हुई**

संजय झा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की नींव कांग्रेस के भरोसे नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के प्रयासों से तैयार हुई थी। इसके लिए वह बंगाल, दिल्ली, लखनऊ और भुवनेश्वर तक गए थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए। संजय झा ने दोहराया कि नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है।

बता दें कि सोनिया गांधी की किताब की किताब में नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी की गई थी। इतना ही नहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार को राजनीति का गिरगिट तक कह दिया था। इसके बाद से ही सियासत गरमा गई। तब से ही जदयू के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं।

## बिहार में दर्दनाक हादसा : एनएच-27 पर बाइक सवार चार दोस्तों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, तीन की मौत, एक घायल

दरभंगा (एजेंसी)

बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मब्बी थाना क्षेत्र के शिवधारा बाजार समिति चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चार दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज स्थित मोमिन टोला निवासी मो. फारिश, मो. इफ्तेखार और मो. अल्ताफ नियाज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त बीती रात बाकरगंज मस्जिद में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद अहले सुबह सभी घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान चारों एक ही बाइक पर सवार होकर एनएच-27 की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शिवधारा बाजार समिति चौक के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा दोस्त घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मब्बी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जबकि तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। मब्बी थानाध्यक्ष अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटे हैं। इसके लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है।

## गैस सिलेंडर लीक होने से तीन दुकानों में लगी आग, तीन लाख से अधिक का नुकसान

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)



बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर थाना क्षेत्र के अति व्यस्त कल्याणी चौक पर बुधवार को गैस सिलेंडर लीक होने से एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की दो अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं और तीन लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई व्यक्ति झुलसा नहीं। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान में चाय बनाने के लिए दूध गर्म किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर की पाइप में आग लग गई। आग फैलते देख दुकानदार ने सिलेंडर को दुकान से बाहर फेंक दिया। उनका कहना है कि अगर समय रहते सिलेंडर को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की तीन दुकानें इसकी चपेट में आ गईं।

जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, तब तक दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार, आग से तीन लाख रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाता तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। लोगों की सूझबूझ से सिलेंडर को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के फायरमैन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि दुकान में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग गई है। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की एक बड़ी और एक छोटी एमटी गाड़ी मौके पर भेजी गई। टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह गैस सिलेंडर से रिसाव होना था।

## नालंदा में रेलवे ट्रैक किनारे मिला मजदूर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

नालंदा (एजेंसी)

बिहार के नालंदा में रेलवे ट्रैक किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार देर शाम तुंगी हाल्ट के पास मिले शव की पहचान 32 वर्षीय मजदूर अजीत कुमार उर्फ कारू पासवान के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और एफएसएल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। वहीं, परिजनों ने इसे ट्रेन हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। घटना बख्तियारपुर-राजगीर रेलखंड पर स्थित तुंगी हाल्ट के पास की है।

मृतक मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया सराय गांव का रहने वाला था। वह स्वर्गीय नरेश पासवान का 32 वर्षीय पुत्र था और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। शव मिलने की सूचना पर सबसे पहले डायल 112 की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दीपनगर थाने की पुलिस और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। अजीत अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गया है। वह चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके तीन भाइयों और पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उसकी मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक के चचेरे भाई और राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी सतेंद्र पासवान ने घटना को दुर्घटना मानने से इनकार किया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि अजीत का किसी से कोई विवाद नहीं था। उनका दावा है कि शव की स्थिति देखकर यह सामान्य ट्रेन हादसा नहीं लगता। उनके अनुसार, ट्रेन की टक्कर होने पर शरीर पर घिसटने या गंभीर चोट के निशान होने चाहिए थे, जबकि अजीत के सिर पर गहरी चोट थी।

## अमेरिकी विशेषज्ञ ने तरंगों से परखी नोएडा एलिवेटेड रोड की मजबूती, अल्ट्रासाउंड गाइडेड वेव्स तकनीक से जांच

नोएडा (एजेंसी)



नोएडा के सेक्टर-27 से 61 के बीच बने 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की जांच पूरी हो गई है। सेक्टर-33 के सामने गड्ढा होने के बाद आईआईटी रुड़की ने जांच शुरू की थी। रोड की मजबूती बिना तोड़फोड़ के परखी गई है। इसके लिए आईआईटी ने अमेरिका से अल्ट्रासोनिक गाइडेड वेव्स तकनीक के विशेषज्ञ को बुलाया था। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, तरंगों के जरिये विशेष परीक्षण किया गया।

इसमें गड्ढे वाले पैनल के अलावा अन्य जगह कमजोरी नहीं मिली। आईआईटी ने आभासी परीक्षण के जरिये मरम्मत का विकल्प तलाशा है। इसमें कम से कम तोड़फोड़ करने पर मंथन हुआ है। बृहस्पतिवार तक आईआईटी की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद नीचे से शटरिंग लगाकर गड्ढे और आसपास के हिस्से की मरम्मत की जाएगी। एलिवेटेड रोड की सेक्टर-61 से सेक्टर-18 की ओर जाने वाली लेन में 18 अक्तूबर को पहली बार गड्ढा हुआ था। प्राधिकरण ने इसे भरवा दिया था। लेकिन 20 अक्तूबर को उसी जगह दोबारा गड्ढा हो गया। इसके बाद 21 अक्तूबर से सेक्टर-61 से सेक्टर-18 की ओर आवागमन बंद है। प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की से जांच कराई है। गड्ढा बिटुमिन की परत में नहीं, बल्कि नीचे बने कंक्रीट के पैनल में हुआ है। यह पैनल 11 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। एलिवेटेड रोड के लिए कंक्रीट के पैनल दूसरी जगह तैयार किए गए थे। बाद में इन्हें निर्माण स्थल पर लगाया गया था। कंक्रीट झड़ने से पूरे एलिवेटेड रोड की मजबूती पर सवाल उठे थे।

इसलिए प्राधिकरण ने विस्तृत जांच कराने का निर्णय लिया। मजबूती जांच के पारंपरिक तरीके में एलिवेटेड रोड की बिटुमिन परत तोड़ी जाती है। इसके बाद नीचे से कंक्रीट के नमूने निकाले जाते हैं। इससे अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। इसलिए आईआईटी ने अल्ट्रासोनिक गाइडेड वेव्स तकनीक से परीक्षण कराने का निर्णय लिया। इसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या कटिंग नहीं हुई। जांच के लिए प्राधिकरण आईआईटी को करीब 15 लाख रुपये का भुगतान करेगा।

यह एक एक आधुनिक गैर-विनाशकारी परीक्षण तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लंबी धातु की पाइपलाइनों और संरचनाओं में जंग या दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह कम आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके एक ही स्थान से दर्जनों मीटर लंबी पाइपलाइन की पूरी दीवार की मोटाई की तेजी से जांच करने में सक्षम बनाती है। प्राधिकरण के इंजीनियरों के मुताबिक, गड्ढे वाले कंक्रीट पैनल के कमजोर होने की वजह निर्माण के दौरान अधिक कंपन हो सकती है। कास्टिंग यार्ड में कंक्रीट के बड़े हिस्से तैयार किए जाते हैं।

## कहीं गूंजे पारंपरिक गीत तो कहीं हुई पूजा, भाइयों की सलामती के लिए बहनों ने रखा व्रत

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)

दीपावली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज पर्व की शहर से लेकर गांव तक धूम है। बुधवार को बहनों ने अपने भाइयों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गोबर से पर्वत बनाकर पूजन किया और लोकगीत गाकर पर्व मनाया। पूजा संपन्न होने के बाद बहनों ने भाइयों को बजरी खिलाई और उनके माथे पर तिलक लगाकर सुखी जीवन की कामना की। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।

यह पर्व भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। पर्व का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से भी माना जाता है। इसी पारंपरिक मान्यता के अनुसार आज भी बहनें पूरे विधि-विधान से पूजा कर इस पर्व को मनाती हैं। पर्व मना रहीं एक महिला व्रती ने बताया कि उन्हें इस दिन का पूरे साल इंतजार रहता है। परिवार के सभी लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। अलग-अलग पूजन सामग्री के साथ पूजा की जाती है। बहनें व्रत रखकर गोबर से पर्वत बनाती हैं और पारंपरिक विधि से पूजन करती हैं। पूजा की सभी रस्में पूरी होने के बाद भाइयों को बजरी खिलाई जाती है और उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। इसके साथ ही भाई दूज का पर्व संपन्न होता है। वहीं, एक अन्य महिला व्रती ने बताया कि आज गोवर्धन पूजा के बाद पूरा समाज एक साथ मिलकर भाई दूज का पर्व मना रहा है। इसमें बड़े-बुजुर्गों से लेकर बच्चे, पुरुष और महिलाएं तक शामिल होते हैं। इस दिन पूजा-पाठ और व्रत करने के पीछे भाई की तरक्की, सुख-शांति, खुशहाली और लंबी उम्र की कामना का भाव है।

## भाई दूज पर हादसे ने छीनी खुशियां : बरेली में दो दोस्तों की मौत, एक अन्य की हालत नाजुक

शाही/बरेली (एजेंसी)



बरेली जिले में भाई दूज से पहले मंगलवार रात शाही-शेरगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों एक ही बाइक से बसावनपुर गांव में लगे दिवाली मेले में जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। शाही थाना क्षेत्र के अमौर गांव निवासी दीपक, मनोज और योगेश दोस्त थे। मंगलवार देर रात तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बसावनपुर गांव में दिवाली मेला देखने जा रहे थे। बताया गया है कि शाही-शेरगढ़ रोड पर खजुरिया चौराहे हनुमान मंदिर के करीब इनकी बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभे पर लगा बिजली तार टूटकर जमीन पर गिर गया और तीनों युवक बाइक से उछलकर खाई में जा गिरे। हादसे के समय बाइक दीपक चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। राहगीरों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में थानाध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक (24 वर्ष) और मनोज (23 वर्ष) ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तीसरे घायल योगेश का बरेली के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके पैर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। दीपक दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। परिवार के भरण-पोषण में पिता का हाथ बंटाते थे। भाई दूज को लेकर दीपक की इकलौती बहन काफी खुश थी, लेकिन भाई की मौत से अब उसके आंसू नहीं थम रहे। मां ममता, पिता केसरी लाल और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मनोज चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे। उन्होंने ऑप्टिकल का कोर्स करने के बाद बरेली में प्रैक्टिस शुरू की थी। तीसरे दोस्त योगेश बीटेक करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर, दो युवकों की मौत की खबर से अमौर गांव में सन्नाटा पसर गया। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए ग्रामीण और रिश्तेदार मृतकों के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को ढाढ़स बंधाया।

## शादी की जिद, शक और गर्भवती होने का ड्रामा, युवक ने प्रेमिका को मारकर किया ये काम, 40 दिन बाद मिला कंकाल

बिजनौर (एजेंसी)



**आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 40 दिन बाद युवती का कंकाल जंगल से बरामद किया। आरोपी ने पिछले डेढ़ वर्षों से संबंध में रही प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। एएसपी देहात गौतम राय ने मंगलवार को बताया कि थाना चांदपुर में आठ नवंबर को गांव कुतुबपुर गांवड़ी निवासी रेखा देवी ने अपनी बेटी राखी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी**

शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका की जेसीबी चालक ने गलाघोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद चाकू से गला काट दिया और शव को गांव बवनपुरा के जंगल में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 40 दिन बाद मंगलवार को युवती का कंकाल जंगल से बरामद किया। आरोपी ने पिछले डेढ़ वर्षों से संबंध में रही प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। एएसपी देहात गौतम राय ने मंगलवार को बताया कि थाना चांदपुर में आठ नवंबर को गांव कुतुबपुर गांवड़ी निवासी रेखा देवी ने अपनी बेटी राखी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि राखी के माता-पिता को लग रहा था कि राखी अपने प्रेमी विकास के साथ शादी कर ली है। इसलिए उन्होंने पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस बीच उन्होंने कई बार राखी को फोन किया लेकिन फोन बंद मिला। पांच दिन पहले राखी के माता-पिता विकास के घर गए और राखी के बारे में पूछा तो विकास ने कहा कि उसे राखी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उसने किसी और के साथ शादी कर ली होगी।

राखी के माता-पिता को विकास पर ही शक था। इसके बाद उन्होंने विकास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर में उन्होंने लिखा कि 28 सितंबर 2026 को उनकी बेटी राखी घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने विकास पर शक जताया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने राखी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गंधौर निवासी विकास के साथ उसकी बातचीत का रिकार्ड सामने आया। पुलिस ने विकास को नौ नवंबर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। एएसपी देहात ने बताया कि विकास जेसीबी चलाता है। वह गांव कुतुबपुर गांवड़ी में किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान करीब डेढ़ साल पहले उसकी गांव की युवती राखी से प्रेम संबंध हो गए। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। बाद में आरोपी राखी से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसीलिसए उसने राखी का फोन उठाना बंद कर दिया। राखी पहले भी दो शादी कर चुकी थी और दोनों को तलाक दे दिया था। विकास को शक था कि राखी का और भी लोगों से संबंध हैं। इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। विकास ने राखी का फोन उठाना बंद कर दिया तो वह 26 सितंबर को विकास के घर पहुंच गई। विकास की पत्नी के सामने राखी ने खुद को गर्भवती बताया। कहा कि अगर विकास उससे शादी नहीं करेगा तो वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देगी। फंसता देख विकास ने दो दिन बाद राखी से फोन पर बात की और घूमने के बहाने उसे बुलाया।

# राष्ट्रपति ट्रंप के नए फैसले से सियासी विवाद, नागरिक अधिकार आयोग में नियुक्ति पर डेमोक्रेट्स नाराज

**न्यूयॉर्क (एजेंसी)**



राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रमुख नागरिक अधिकार एजेंसी में खाली पड़ी सीट के लिए न्याय विभाग के एक अधिकारी को नामित किया है। इससे पता चलता है कि उनका प्रशासन उन 'विविधता नीतियों' (डायवर्सिटी पॉलिसी) को खत्म करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे श्वेत कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव करती हैं।

व्हाइट हाउस ने सोमवार देर रात घोषणा की कि उन्होंने मैट जैंडी को उस सीट पर नियुक्त करने का फैसला किया है, जिस पर पहले जोसेलिन सैमुअल्स थीं। सैमुअल्स उन दो डेमोक्रेटिक आयुक्तों में से एक थीं, जिन्हें ट्रंप ने उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही हटा दिया था। यह एक अभूतपूर्व कदम था, जिसका उद्देश्य ईईओसी (समान रोजगार अवसर आयोग) पर नियंत्रण हासिल करना था। ईईओसी एक द्विदलीय एजेंसी है, जिसे कांग्रेस ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (सिविल राइट्स एक्ट) के तहत बनाया था। जैंडी वर्तमान में न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग में 'चीफ ऑफ स्टाफ' के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रभाग में काम करने वाले कई अनुभवी वकीलों ने तब इस्तीफा दे दिया था, जब विभाग ने नियोक्ताओं और स्कूलों की जांच शुरू की। विभाग का मानना है कि उनकी 'विविधता' और 'ट्रांसजेंडर' नीतियां गैर-कानूनी हैं। अगर जैंडी की नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है, तो वे पांच साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जो 1 जुलाई, 2031 को समाप्त होगा।

जैंडी की नियुक्ति से ईईओसी में सत्ता का संतुलन और अधिक 'दक्षिणपंथी' (रिपब्लिकन विचारधारा की ओर) हो जाएगा। वर्तमान में, वहां दो रिपब्लिकन आयुक्त हैं - एंड्रिया लुकास (जो अध्यक्ष हैं) और ब्रिटनी पैनुशियो - और एक डेमोक्रेट आयुक्त हैं - कल्पना कोटागल, जिनका कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है लुकास के नेतृत्व में, ईईओसी ने ट्रंप की नागरिक अधिकारों से जुड़ी प्राथमिकताओं को सख्ती से लागू किया है, जिसमें अक्सर न्याय विभाग का भी पूरा सहयोग मिला है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक पांचवीं सीट भरने के लिए किसी को नामित नहीं किया है। यह सीट डेमोक्रेट शार्लोट बरोज को हटाए जाने के बाद से खाली पड़ी है। जनवरी में सीनेट में डेमोक्रेट्स का बहुमत आने की संभावना है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रंप के कार्यकाल के बचे हुए समय में ईईओसी में पांच कमिश्नर नहीं होंगे। प्रमुख डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने कसम खाई है कि वे ईईओसी के लिए ट्रंप द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति की पुष्टि नहीं करेंगे। उनका विरोध डेमोक्रेटिक कमिश्नरों को हटाए जाने को लेकर है। उनका कहना है कि इस कदम ने एजेंसी की ऐतिहासिक स्वतंत्रता और दोनों दलों की भागीदारी को खत्म कर दिया है।

### डेमोक्रेटिक सीनेट ने क्या कहा?

विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने जैंडी के नामांकन की आलोचना करते हुए कहा कि इससे ईईओसी का और अधिक राजनीतिकरण हो रहा है। बता दें कि ईईओसी देश में रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव रोकने वाले कानूनों को लागू करने का काम करता है। मंगलवार को सीनेट समिति की एक सुनवाई के दौरान, बाल्डविन ने कहा, 'दोनों दलों की भागीदारी वाले आयोग में, यह परंपरा रही है कि दोनों पार्टियों से नामित लोगों को एक साथ रखा जाए। यह लगातार तीसरा मौका है जब किसी रिपब्लिकन कमिश्नर को बिना किसी जोड़ीदार (दूसरे दल के प्रतिनिधि) के नामित किया गया है। यह प्रशासन का पूरी तरह से पक्षपाती फैसला है।' यह सुनवाई कैथरीन एशबैक को ईईओसी का जनरल काउंसिल नियुक्त करने की पुष्टि के लिए हो रही थी। हालांकि, ईईओसी को लेकर ट्रंप के दृष्टिकोण को तब एक बड़ा समर्थन मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के उनके फैसले को सही ठहराया। इस फैसले से राष्ट्रपति की शक्तियों का काफी विस्तार हुआ है। इस फैसले के बाद सैमुअल्स ने ईईओसी से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाला मुकदमा वापस ले लिया। जब तक सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है, तब तक जैंडी और एशबैक की नियुक्ति की पुष्टि होने की पूरी संभावना है। सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने नागरिक अधिकारों को लागू करने के ट्रंप के तरीके की काफी तारीफ की है।

## हादसा या साजिश? : एसयूवी कार की टक्कर से लॉस एंजिलिस में तीन की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

**लॉस एंजिल्स (एजेंसी)**




अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिलिस में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां नॉर्थ हॉलीवुड में मेट्रो स्टेशन के पास फुटपाथ पर चल रहे लोगों को एक तेज रफ्तार सफेद एसयूवी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। लॉस एंजिलिस अग्निशमन विभाग (एलएएफडी) ने इसकी जानकारी दी। लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग (एलएपीडी) के मुताबिक, व्यस्त चौराहे पर शाम करीब छह बजे से ठीक पहले एक सफेद एसयूवी ने कम से कम पांच लोगों को टक्कर मारी।

अधिकारियों ने बताया कि कम से कम तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें वाहन का चालक भी शामिल है। फिलहाल अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है। मंगलवार रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलएपीडी के कैप्टन वार्नर कैस्टिलो ने कहा, 'हमें नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या दुर्घटनावश हुआ।' कैस्टिलो के मुताबिक, एसयूवी चालक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। उसकी उम्र 60 साल के आसपास है। अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए उसकी चिकित्सकीय जांच शुरू की है कि कहीं वह नशे के प्रभाव में तो वाहन नहीं चला रहा था। लॉस एंजिलिस की मेयर करेन बास ने बताया कि हादसे के शिकार लोगों में सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेता और राहगीर शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया। मेयर ने लिखा, 'इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के लिए मेरा दिल दुखी है।' वहीं, एलएपीडी के प्रमुख जिम मैकडॉनेल ने बताया कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी।

## ईरान ने फ्रांस के आरोप को नकारा, बोला - साइबर हमले से कोई लेना-देना नहीं

**तेहरान/पेरिस (एजेंसी)**



ईरानी विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के लगाए साइबर अटैक आरोप को 'बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण' बता कर खारिज कर दिया है। फ्रांस ने अक्टूबर में सैकड़ों सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हुए साइबर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। मंगलवार (स्थानीय समय) को जारी एक बयान में, मंत्रालय ने इसे 'घिसी-पिटी' नीति बताते हुए निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि यह नया आरोप उन पुराने दावों की ही एक कड़ी है, जिसका मकसद फ्रांस की ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र के प्रति 'विनाशकारी नीतियों' से लोगों का ध्यान भटकाना है। मंत्रालय ने इसे एक 'गैर-जिम्मेदाराना और बचकाना कदम' बताया, जिसका उद्देश्य ईरान की छवि खराब करना और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों में खटास पैदा करना है।

मंत्रालय ने कहा कि 'अवैध विदेशी गतिविधियों' के सामने अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए ईरान 'जरूरी और उचित' कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने सोमवार को कहा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाकर किए गए साइबर हमले के लिए ईरान का 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' जिम्मेदार है। पेरिस में 'ग्रुप ऑफ सेवन' (जी7) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, बैरोट ने कहा कि फ्रांस ने इस हमले पर 'कड़ा विरोध' दर्ज कराने के लिए पेरिस में ईरानी राजदूत को तलब किया है। इस बीच, इटली के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि हाल ही में कई यूरोपीय देशों को प्रभावित करने वाले साइबर हमलों के मद्देनजर, इटली साइबर सुरक्षा समन्वय, सूचना साझा करने और सिस्टम सुरक्षा में निवेश को लेकर गंभीर है और इसे और सुदृढ़ करने का काम करेगा। ये कदम गृह मंत्री माटेओ पियांटेदोसी की अध्यक्षता में 'नेशनल कमिटी फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी' की बैठक में तय किए गए।

## बांग्लादेश में हिंसा : बस को उपद्रवियों ने जलाया, चालक की मौत

**ढाका (एजेंसी)**



बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक देश के करीब 21 जिलों में आगजनी की घटनाएं सामने आईं। बसों और ट्रेन के कोच में आग लगाई गई। सरकारी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों के गेट भी बंद कर दिए गए। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, सोमवार देर रात फरीदपुर शहर के गोलाचामट इलाके में एक बस को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक, बाइक पर तीन लोग आए थे।

इनमें से एक ने बस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। घटना के समय बस ड्राइवर मोहम्मद कलाचन अंदर सो रहे थे। आग लगने के बाद वे बाहर निकले, लेकिन धुएं से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कलाचन गोपालगंज जिले के मुक्सुदपुर उपजिला के दिगनगर गांव के रहने वाले थे। पुलिस को शक है कि हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग से है। पुलिस के मुताबिक, हसीना की बांग्लादेश वापसी की घोषणा के बाद ही हिंसक गतिविधियों में इजाफा हुआ। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। वहीं, अवामी लीग ने पुलिस के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद अली आराफात ने दावा किया कि विरोधी गुट पार्टी को बदनाम करने और हमलों का आरोप उस पर डालने के लिए ये घटनाएं करवा रहे हैं।

न्यूज एजेंसी बीएसएस ने बताया कि बांग्लादेश पुलिस और ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 11 जिलों में 22 वाहनों को आग लगाई गई। ढाका और छह अन्य जिलों में कम से कम 28 जगह देसी बम धमाकों की घटनाएं हुईं। राजधानी ढाका में देसी बम धमाकों और आगजनी की घटनाएं जारी रहीं। मंगलवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को दिन और रात में कई जगहों पर धमाके हुए। हाल के हमलों के निशानों में ढाका यूनिवर्सिटी का टीचर-स्टूडेंट सेंटर, कोर्ट परिसर, शिक्षण संस्थान और भीड़भाड़ वाले चौराहे शामिल थे। सोमवार शाम को फार्मगेट मेट्रो रेल स्टेशन के नीचे एक बस में आग लगा दी गई, जबकि बनाश्री, श्यामपुर, मीरपुर और अन्य इलाकों में भी अलग-अलग धमाके हुए। ये घटनाएं रविवार को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस, मालिबाग में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) मुख्यालय के पास और पुलिस ठिकानों पर हुए धमाकों के बाद सामने आई हैं। पुलिस ने कुछ हमलों के सिलसिले में संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, पुलिस ने बिना फटे देसी बम और ऐसी सामग्री भी बरामद की है, जिनका इस्तेमाल शायद आगे की घटनाओं के लिए किया जाना था। हालांकि, जांचकर्ता अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि क्या ये सभी हमले आपस में जुड़े हुए थे या इन्हें किसी एक ही समूह द्वारा अंजाम दिया गया था। मंगलवार सुबह गोपालगंज के टुंगीपाड़ा में तनाव बढ़ गया।

सुबह करीब 9:30 बजे प्रतिबंधित छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने गोहारडांगा चौरंगी चौराहे पर सामान जलाकर सड़क जाम कर दी। बाद में अवामी लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ता भी उनके साथ शामिल हो गए। प्रदर्शनकारी जब पाटगाती बाजार की ओर जुलूस निकाल रहे थे, तब एक स्थानीय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) कार्यालय के बाहर लगे कई बैनर और सजावटी पट्टियां तोड़ दी गईं। पुलिस ने जुलूस रोकने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई।

## पंजाब में 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला, छह जिलों में नए डीसी नियुक्त

**चंडीगढ़ (एजेंसी)**

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके साथ ही राज्य के छह जिलों में नए उपायुक्त (डीसी) नियुक्त किए गए हैं। मंगलवार को कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, छह आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि कई अन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर स्थानांतरित किया गया है।

मोहाली की उपायुक्त रहीं कोमल मित्तल को रोपड़ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने आदिया डचवाल की जगह ली है। हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना का नया उपायुक्त बनाया गया है, जहां उन्होंने हिमांशु जैन का स्थान लिया है। अभिजीत कपलीश को बरनाला का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। उनके पास बरनाला नगर निगम के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। आदिया डचवाल को मोहाली का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि हिमांशु जैन को पटियाला का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने हिमांशु अग्रवाल की जगह ली है। निर्मल ओसेपाचन को तरनतारन का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वे पहले मुख्य सचिव के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव (समन्वय) और विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्यरत थे। अन्य प्रशासनिक बदलावों के तहत, राहुल गुप्ता को परिवहन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें 'मिल्कफेड' के प्रबंध निदेशक (एमडी) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं, अनुपम क्लेर को रक्षा सेवा कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हरप्रीत सिंह को खेल और युवा सेवा विभाग का निदेशक बनाया गया है, जबकि मनीषा राणा सूचना प्रौद्योगिकी/औद्योगिक संवर्धन विभाग की निदेशक का कार्यभार संभालेंगी।

## भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष जनजातीय समाज की प्रेरणा, मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को दी नई दिशा : नेगी

**शिमला (एजेंसी)**




भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेगी ने शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में देशभर में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं।

सुनील नेगी ने कहा कि 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष के जीवनकाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष किया और जनजातीय समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उनका उलगुलान आंदोलन अन्याय, शोषण और विदेशी शासन के विरुद्ध जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक बना। उनका जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक हैं, जो कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत हैं। देश में 700 से अधिक जनजातीय समुदाय तथा 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। नेगी ने बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान प्रदेशभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, जनजागरण कार्यक्रम तथा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

सोशल मीडिया और विभिन्न जनसंपर्क माध्यमों से युवाओं को जनजातीय महापुरुषों के योगदान से परिचित करवाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा जनजातीय मोर्चा के प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सुनील नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना जनजातीय कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने को भी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

## कर्नाटक : पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने प्रियांक खड़गे को लिखा पत्र, 'आरएसएस पर बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना'

**बेंगलुरु (एजेंसी)**

बेंगलुरु के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रियांक खड़गे को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे गृह विभाग की प्रतिष्ठा को कम न करें। साथ ही विभाग और कर्नाटक पुलिस की गरिमा, मर्यादा व संस्थागत अखंडता को बनाए रखें।

भास्कर राव ने संघ को निशाना बनाते हुए प्रियांक खड़गे के हालिया बयानों, विशेष रूप से नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्याओं के संबंध में टिप्पणियों पर चिंता जताई। उन्होंने पत्र में लिखा, 'आपका यह बयान कि 'संघ वालों ने उन्हें मारा', जिसमें आप सीधे तौर पर इन हत्याओं के लिए संघ के सदस्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना है। केवल राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए इस तरह के व्यापक आरोप नहीं लगाए जा सकते।' उन्होंने कहा, आपराधिक जांच सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, और अपराध की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। एक जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक आरोपों, जांच के निष्कर्षों और न्यायिक फैसलों के बीच का अंतर समझना चाहिए। भास्कर राव ने कहा कि गृह मंत्री किसी विशेष आपराधिक जांच के प्रवक्ता नहीं बन सकते, लंबित मामलों में खुद कोई निष्कर्ष नहीं सुना सकते और न ही जांच अधिकारियों व अदालतों के निष्कर्षों की जगह अपनी राजनीतिक राय रख सकते हैं। गृह मंत्री न तो जांच अधिकारी की भूमिका निभा सकते हैं और न ही अपने पद के अधिकार का उपयोग करके किसी विशेष आपराधिक मामले के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।

## असम में हुए रेल हादसे में सभी यात्री सुरक्षित, 4 को मामूली चोटें : सीएम हिमंता



**गुवाहाटी (एजेंसी)**

गुवाहाटी के पास दिगारू में बुधवार सुबह कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'सभी यात्री सुरक्षित हैं। 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। हम इस स्थिति को लेकर रेल मंत्रालय (भारत) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फंसे हुए सभी यात्रियों को जरूरी चीजें उपलब्ध करा दी गई हैं और उनकी आगे की यात्रा के लिए एक दूसरी ट्रेन का इंतजाम कर दिया गया है।' इससे पहले, भारतीय रेलवे ने इस घटना को लेकर विस्तृत जानकारी शेयर की।

रेलवे के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह लगभग 6.54 बजे हुई, जब कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 13125) को असम के दिगारू रेलवे स्टेशन पर किसी दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए रोका जा रहा था। उसी समय लोको पायलट ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें इंजन और 5 कोच पटरी से उतर गए। भारतीय रेलवे ने शुरुआत में बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने कहा, राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। एन. एफ. रेलवे के महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, ताकि बहाली के काम की निगरानी की जा सके। भारतीय रेलवे ने यह भी जानकारी दी कि ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण दो ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इनमें ट्रेन संख्या 12067 (गुवाहाटी-जोरहाट टाउन) जन शताब्दी एक्सप्रेस को पानबारी में रोका गया है। वहीं, ट्रेन संख्या 15627 (कोयंबटूर-सिलचर) एक्सप्रेस को पानीखैती में रोका गया है।

## मस्तक पर वैष्णव तिलक और गणेश से सजे बाबा महाकाल, गले में पहनी रुद्राक्ष की माला फिर रमाई भस्म

**उज्जैन (एजेंसी)**



विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बुधवार की सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया।

इस दौरान भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत को अर्पित कर किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई। बुधवार के श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि बुधवार बाबा महाकाल का वैष्णव तिलक और गणेश से श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल गले मे रुद्राक्ष की माला पहनकर सजे और फिर भस्म रमाई। आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या मे श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगे।

## शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदार के कपाट, सेना के बैंड की धुनों के बीच दी विदाई

**रुद्रप्रयाग (एजेंसी)**



विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे। इस दौरान बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को विदा करने के लिए भारतीय सेना का बैंड भी मौजूद रहा। इससे पहले, केदारनाथ धाम में इस यात्रा वर्ष की अंतिम संध्याकालीन आरती श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। आरती के बाद भारतीय सेना के बैंड ने मधुर धुनों से पूरे धाम को भक्तिमय बना दिया। मुख्य पुजारी ने श्रद्धालुओं के माथे पर आरती की पवित्र भस्म लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबा के जयकारों से पूरी केदारपुरी गुंजायमान हो उठी। इस वर्ष बाबा केदार के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस यात्रा वर्ष में कुल 19 लाख 22 हजार 138 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा का समापन हो गया है। अब शीतकाल में बाबा केदार की पूजा-अर्चना परंपरानुसार उनके शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में संपन्न होगी।

बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अब शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हो गई है। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से बाबा को विदाई दी और अगले यात्रा वर्ष में पुनः दर्शन करने की कामना की। डोली को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया गया। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, अगले छह महीनों तक भगवान की पूजा वहीं की जाएगी। इस बीच, चार धाम यात्रा भी इस साल अपने समापन की ओर है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अधिक ऊंचाई पर स्थित इन तीर्थस्थलों तक पहुंचना काफी कठिन हो जाता है। श्री गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को बंद हो गए, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 13 नवंबर को बंद होंगे। इसके साथ ही इस सीजन की वार्षिक चार धाम यात्रा संपन्न होगी।

# बांग्लादेश महिला टीम की फिटनेस और अनुशासन पर सरोवर इमरान ने सवाल उठाए

**नई दिल्ली (एजेंसी)**



बांग्लादेश महिला टीम के पूर्व हेड कोच सरोवर इमरान ने टीम के फिटनेस स्तर और ट्रेनिंग कल्चर पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि खिलाड़ियों को उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने और ज्यादा अनुशासन लाने की उनकी कोशिशों की वजह से उन्हें अपनी भूमिका से अलग होना पड़ा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एशियन गेम्स के बाद अक्टूबर में सरोवर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने दिया और बाद में उनकी जगह डेविड हेम्प को नियुक्त किया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीबी से सरोवर इमरान की शिकायत की थी और उनके तरीकों पर सवाल उठाया था। सरोवर ने पहले बांग्लादेश के एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद ड्रेसिंग रूम में अशांति की बात कही थी, जिसके बाद बोर्ड ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार किया। प्रस्तावित कार्रवाई को आखिरकार वापस ले लिया गया, जिसमें बीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट के साथ उनके लंबे जुड़ाव को ध्यान में रखा। सरोवर ने कहा कि बोर्ड ने उन्हें जारी रखने का फैसला करने से पहले कभी उनसे सफाई नहीं मांगी। उन्होंने कहा, एशियन गेम्स और एशिया कप के बाद बीसीबी ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। मुझे एक पत्र मिला कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि कोई दूसरा कोच जाएगा। बीसीबी के साथ मेरी बस इतनी ही बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कोचिंग का माहौल बहुत ज्यादा संतुलन बनाने वाला हो गया था, जिससे सुधार की बहुत कम गुंजाइश बची थी। महिला टीम में शामिल होने के बाद अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक मेरे गुस्से की बात है, जब मैं महिला टीम में आया, तो मैंने देखा कि गेंदबाजी कोच से लेकर स्पिन बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, ट्रेनर और फिजियो सभी बहुत शांत थे। वे महिला क्रिकेटरों की हर बात सुनते हैं और इस कम्फर्ट जोन में रहकर वे सुधार नहीं कर सकते।

यही वजह है कि हमारी टीम आज भी वैसी ही है जैसी पांच साल पहले थी। इमरान ने कहा, एक स्पिनर 30 गेंदें फेंकने के बाद कोच से कहती है कि वह अब और गेंदबाजी नहीं करेगी और कोच मान जाता है। एक या दो बल्लेबाज पूरे दिन बल्लेबाजी करते हैं। यह सब देखने के बाद मैंने दखल देना शुरू कर दिया। मैंने उनकी फिटनेस को लेकर भी दखल दिया। उन्होंने कहा, जब मुझे उन्हें डांटने की जरूरत थी तो मैंने वैसा ही किया और अगर आप कहते हैं कि यह गुस्सा है तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट सुधर सकता है। मुझे लगा कि मैं उन्हें सुधार सकता हूं और मैंने सात से आठ टूर किए और सब कुछ सिर्फ एक या दो टूर में फेल होने की वजह से खत्म हो गया। सरोवर ने इस बात को मना कर दिया कि उनकी कोचिंग स्टाइल उनके गुस्से को कंट्रोल करने में नाकामयाबी दिखाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के लिए कभी-कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। सरोवर ने कहा, मेरी अपनी इज्जत है और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं दिखावे के लिए काम नहीं करता। मुझे कोई समस्या नहीं है और ऐसा महसूस करने की कोई वजह नहीं है कि मेरी इज्जत कम हो गई है क्योंकि मैं अपना काम जानता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं गुस्से वाला हूं तो यह गलत है क्योंकि जिंदगी में मुझे गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब मैं कोचिंग कर रहा होता हूं तो मैं गुस्से वाला नहीं होता क्योंकि मैं एक पेशेवर हूं और मुझे पता है कि क्या करना है।

एक कोच किसी खिलाड़ी का दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं किसी खिलाड़ी का दोस्त हूं तो मैं खिलाड़ी को हटा नहीं सकता। मैं एक कोच हूं और मैं उनका दोस्त नहीं हूं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने खिलाड़ियों को कम्फर्टेबल रखने को प्राथमिकता दी। इमरान ने कहा, मुझे लगता है कि जिसने भी उनके (महिला क्रिकेटरों) साथ काम किया, उसने उनके साथ एडजस्ट किया, लेकिन महिला क्रिकेटर अगर कम्फर्ट जोन में रहेंगी तो बेहतर नहीं होंगी और मुझे लगा कि विदेशी कोचों ने भी ऐसा ही किया। मुझे लगता है कि एक कोच ऐसा करके अपना काम पक्का करता है।

# साल 2027 में तय किया जाएगा 'पैरालंपिक गेम्स' के लिए खेल कार्यक्रम

**बर्लिन (एजेंसी)**



अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) अप्रैल 2027 में 2032 खेलों के लिए खेल कार्यक्रम को अंतिम रूप देने जा रही है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के गवर्निंग बोर्ड ने ब्रिसबेन 2032 पैरालंपिक गेम्स के खेल कार्यक्रम को 2027 में तय करने का फैसला किया है। पहले यह उम्मीद थी कि इसे 2026 के अंत तक तय कर लिया जाएगा। पैरालंपिक गेम्स के खेल कार्यक्रम को तय करने की प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की खेल कार्यक्रम प्रक्रिया से अलग है।

हालांकि, ओलंपिक खेल कार्यक्रम और उससे जुड़े वेन्यू मास्टरप्लान का असर उन कारकों पर पड़ सकता है, जिन पर आईपीसी गवर्निंग बोर्ड पैरालंपिक खेल कार्यक्रम के बारे में फैसला लेते समय विचार कर सकता है - जैसे कि लागत, जटिलता और आयोजन समिति पर पड़ने वाला प्रभाव, लेकिन आईपीसी गवर्निंग बोर्ड अपना फैसला 2027 के दौरान ही लेगा। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की हालिया घोषणा के बाद आया है, जिसमें एक संशोधित समय-सीमा तय की गई है। आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने अप्रैल 2027 में ब्रिसबेन 2032 ओलंपिक खेल कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए इस समय-सीमा को मंजूरी दी है। आईपीसी ने 2025 के अंत में ब्रिसबेन 2032 पैरालंपिक खेल कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महासंघों और मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय महासंघों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ब्रिस्बेन 2032 पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर, 2032 के बीच आयोजित किए जाएंगे। जर्मनी के बर्लिन में पैरालंपिक आंदोलन से जुड़े 250 से अधिक नेता 'इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी (आईपीसी) मेंबरशिप गैदरिंग' के लिए इकट्ठा हुए। तीन दिनों तक चले इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा आपसी सहयोग, जानकारी साझा करने और पैरा खेलों के भविष्य को आकार देने पर था। 'कमिंग टुगेदरः अ कॉल टू एक्शन' थीम पर आधारित यह कार्यक्रम 7 से 9 नवंबर तक आयोजित किया गया।

इसमें नेशनल पैरालंपिक कमेटियों, अंतरराष्ट्रीय महासंघों, विकलांगों के लिए खेल से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, क्षेत्रीय संगठनों और आईपीसी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने पैरालंपिक आंदोलन के सामने आने वाले मौकों और चुनौतियों पर चर्चा की, क्योंकि अब यह आंदोलन एक नए रणनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा है।

# आईसीसी टेस्ट रैंकिंग : रहमत शाह ने रचा इतिहास, टॉप-10 में जगह बनाने वाले पहले अफगान खिलाड़ी बने

**दुबई (एजेंसी)**



अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने इतिहास रच दिया है। वे आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाले देश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद वे सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट की किसी भी श्रेणी में टॉप-10 में जगह बनाने वाले पहले अफगान क्रिकेटर बन गए हैं।

दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में 173 रन बनाने के बाद रहमत छह पायदान ऊपर चढ़े, जिससे उन्हें करियर की सबसे अच्छी रेटिंग मिली और वे भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और श्रीलंका के कामिंदू मेंडिस जैसे बल्लेबाजों से आगे निकल गए। 33 साल के रहमत की यह पारी टेस्ट क्रिकेट में उनकी पांचवीं सेंचुरी और इस साल की दूसरी सेंचुरी थी। इस महीने की शुरुआत में, टीम आईसीसी मेन्स वनडे टीम रैंकिंग में अपनी अब तक की सबसे ऊंची जगह (छठे नंबर) पर पहुंच गई। जिम्बाब्वे के क्रेग इरविन को भी हालिया टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह टेस्ट की दूसरी पारी में डबल सेंचुरी बनाने वाले इरविन नौ स्थान ऊपर चढ़कर 48वें नंबर पर पहुंच गए। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के खत्म होने से भी बैटिंग रैंकिंग में काफी बदलाव आया। वेस्टइंडीज के कावेम हॉज 12 जगह ऊपर चढ़कर 52वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि बांग्लादेश के तौहिद हृदॉय 60वें नंबर पर पहुंचे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आमिर जंगू 28 पोजीशन ऊपर चढ़कर 62वें नंबर पर पहुंच गए।

गेंदबाजों में, वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन ने बांग्लादेश के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस के बाद करियर की सबसे ऊंची रेटिंग हासिल की। वह टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 11 पायदान ऊपर चढ़कर 19वें नंबर पर आ गए और ऑलराउंडर्स में चार पायदान ऊपर चढ़कर 31वें नंबर पर आ गए। उनके साथी जस्टिन ग्रीव्स को भी फायदा हुआ है। वह एक स्थान आगे बढ़कर टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आठवें नंबर पर आ गए। भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के शुरुआती दो मैचों के बाद ताजा वनडे रैंकिंग में भी कई खिलाड़ियों को फायदा हुआ है।

भारत के स्पिनर अक्षर पटेल वेलिंगटन में दूसरे मैच में 2/28 विकेट लेने के बाद वनडे गेंदबाजों में 23 पायदान ऊपर चढ़कर 21वें नंबर पर आ गए। ऑकलैंड में सीरीज के पहले मैच में चार विकेट लेने के बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 11 पायदान ऊपर चढ़कर 31वें नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टॉप-100 से बाहर रहे युवा भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार 2 मैचों में 7 विकेट लेकर 48वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

# एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की ट्रॉफी का खेल मंत्री विश्वास सारंग ने किया अनावरण

**भोपाल (एजेंसी)**



विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के नाथू बरखेड़ा में बने नए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होना है। राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण बुधवार को किया और हरी झंडी दिखाकर टूर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर विश्वास सारंग ने मीडिया से कहा, मध्यप्रदेश में खेलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयासरत हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि नाथू बड़खेड़ा में हमारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पहला चरण बनकर तैयार है। अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर का उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से ही हो रहा है।' उन्होंने कहा, 'एशियन विमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हम 19 नवंबर को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार है कि हर आयोजन में हम अवसर ढूंढें, इसलिए ये आयोजन सिर्फ एक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन ही नहीं है जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हम मध्यप्रदेश और भोपाल में हॉकी की चमक को स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन कर रहे हैं।

हमने ट्रॉफी को जनता के बीच प्रदर्शित किया है। पूरे प्रदेश में ट्रॉफी का टूर कराया जाएगा। मुख्यालयों में बड़े-बड़े कार्यक्रम होंगे। इसमें जन प्रतिनिधि और हॉकी से जुड़े खिलाड़ी उपस्थित होंगे। सारंग ने कहा, हमने ट्रॉफी टूर रथ को भोपाल से शुरू किया है। ट्रॉफी टूर 17 नवंबर तक चलेगा। 12 नवंबर से 19 नवंबर तक ये सप्ताह पूर्णतः हम हॉकी को समर्पित करेंगे। आयोजन के पहले प्रदेश में हॉकी के प्रति सकारात्मक माहौल बने, युवाओं में आकर्षण बढ़े और हॉकी से जुड़े खिलाड़ियों को इस आयोजन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिले। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया है। ट्रॉफी के प्रदर्शन के समय राज्य के युवा खिलाड़ी बड़ी संख्या में हॉकी के साथ उपस्थित थे। विश्वास सारंग ने ट्रॉफी का अनावरण युवा खिलाड़ियों के बीच बैठकर किया।

ट्रॉफी को राज्य टूर के लिए विशेष वाहन पर खेल मंत्री सारंग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और साउथ कोरिया शामिल होंगे।

**विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के लिए भारतीय टीमः**
**गोलकीपरः** बंसरी सोलंकी, बीचू देवी खारीबाम, **डिफेंडरः** निक्की प्रधान, ज्योति, ज्योति सिंह, सुशीला चानू लालथंतलुआंगी, पूजा साहू, मिडफील्डरः रुतुजा दादासो पिसल, सुनीता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, साक्षी राणा, बलजीत कौर, इशिका, फॉरवर्डः नवनीत कौर, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग, लालरेमसियामी, मुमताज खान।

# हार्दिक ने एमआई के साथ खास पल बिताए, अर्शदीप गेंदबाजी को मजबूती देंगे : आकाश अंबानी

**मुंबई (एजेंसी)**

मुंबई इंडियंस ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि हार्दिक पंड्या अब टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते नजर आएंगे। वहीं, ट्रेड के माध्यम से अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं।

मुंबई इंडियंस अपने सोशल मीडिया पर भी हार्दिक के टीम से जाने और अर्शदीप सिंह से टीम में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। एमआई के ओनर आकाश अंबानी ने कहा, 'हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के साथ कुछ बहुत ही खास पल बिताए हैं। हमने उन्हें एक क्रिकेटर के तौर पर आगे बढ़ते, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाते और फिर टीम को लीड करते हुए देखा है। उनका योगदान, उनकी ऊर्जा और मैदान पर उनके साथ आने वाली प्रतियोगी भावना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कीमती रही है। मैं एक क्रिकेटर और एक इंसान के तौर पर उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और आगे जो कुछ भी होगा, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुंबई इंडियंस इतने वर्षों में टीम में हार्दिक के अहम योगदान को मानती है। 2015 में एक युवा क्रिकेटर के तौर पर एमआई में शामिल होने के बाद, हार्दिक दुनिया के शीर्ष ऑलराउंडर्स में से एक बन गए। 2024 में कप्तान के तौर पर फ्रेंचाइजी में लौटने से पहले उन्होंने चार आईपीएल खिताब जीतने वाले कैंपेन में अहम भूमिका निभाई है। मुंबई इंडियंस हार्दिक की प्रतिबद्धता, योगदान और इतने वर्षों में साझा किए गए कई यादगार पलों के लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है, और उनके करियर के अगले चैप्टर में उनकी हर सफलता की कामना करते हैं।

# हार्दिक पंड्या को विदाई और अर्शदीप का स्वागत, मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर साझा किया पोस्ट

**मुंबई (एजेंसी)**



आईपीएल 2024 से आईपीएल 2026 तक मुंबई इंडियंस (एमआई) के कप्तान रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाता अब इस टीम से टूट चुका है। एमआई ने सोशल मीडिया पर हार्दिक को उनके आगे के सफर के लिए शुभकामना भी दे दिया है। साथ ही एमआई ने अपने साथ जुड़े अर्शदीप सिंह का स्वागत किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमआई ने कई पोस्ट साझा करते हुए अपने कप्तान हार्दिक को बधाई दी है। एमआई ने अपने सबसे पहली पोस्ट में लिखा, हार्दिक, ब्लू एंड गोल्ड को जोश और गर्व के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए धन्यवाद। हम आपको आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। एक अन्य पोस्ट में हार्दिक की प्रशंसा में एमआई ने लिखा, 'उतार-चढ़ाव के बीच, मुंबई इंडियंस की कहानी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, हार्दिक।' हार्दिक पंड्या आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। वह ट्रेड डील के तहत 18 करोड़ में पंजाब से जुड़े हैं। 2019 से पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। एमआई ने पंजाब किंग्स से हार्दिक के बदले अर्शदीप सिंह को अपने साथ जोड़ा है। अर्शदीप भी 18 करोड़ में एमआई से जुड़ें हैं।

एमआई ने सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह की एक छोटी वीडियो साझा करते हुए टीम में उनका स्वागत किया है। एक अन्य पोस्ट में एमआई ने जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की फोटो साझा करते हुए लिखा है, प्रिय बल्लेबाजों, स्टंप उड़ेंगे, किनारे उड़ेंगे। उंगलियां ऊपर जाएंगी। और वो पैर की उंगलियां? बेहतर होगा कि उन्हें बचाकर रखें। यह कॉम्बो जल्द ही जोड़ों में शिकार करेगा, सिर्फ टी20 आई में ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करती है और दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी मानी जाती है।

इन दोनों को साथ पाकर मुंबई इंडियंस बेहद खुश है। पंजाब किंग्स ने भी एक्स पर अर्शदीप सिंह के टीम से अलग होने की जानकारी देते हुए लिखा, एक युवा शेर से एक ऐसा नाम जिसने पंजाब को गर्व महसूस कराया। अर्शदीप, यहां हमेशा आपका घर रहेगा।

## हार्दिक का आना आईपीएल खिताब की तरफ एक जरूरी कदम : पंजाब किंग्स सीईओ सतीश मेनन

**नई दिल्ली (एजेंसी)** पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के सीईओ सतीश मेनन ने बुधवार को प्रीमियर सीम-बॉलिंग ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या को साइन करने को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टाइटल जीतने की फ्रेंचाइजी की कोशिश में एक जरूरी कदम बताया। बीसीसीआई ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि पंड्या मुंबई इंडियंस (एमआई) से एक ट्रेड डील में पंजाब किंग्स में शामिल हुए। डील के तहत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए। ट्रेड प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह से चल रही थी। पंजाब किंग्स अभी तक कोई आईपीएल खिताब नहीं जीता है। उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 और 2025 में रहा है, जब टीम फाइनल में पहुंची थी। मेनन ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'हमें हार्दिक का पंजाब किंग्स परिवार में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

वह एक साबित मैच-विनर है, जो जबरदस्त अनुभव, आत्मविश्वास और जीतने की सोच लेकर आए है। बैट और बॉल दोनों से गेम का रुख बदलने की उनकी काबिलियत उन्हें हमारी टीम के लिए एक कीमती बनाती है। हम आईपीएल के 20वें सीजन में कदम रख रहे हैं, हमारा फोकस एक ऐसी टीम बनाने पर है जो सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला कर सके और ट्रॉफी पंजाब घर ला सके। हार्दिक का आना उस दिशा में एक जरूरी कदम है। मेनन ने अर्शदीप के पंजाब किंग्स से मुंबई इंडिया का हिस्सा बनने पर कहा, 'अर्शदीप कई सालों से पंजाब किंग्स का अहम हिस्सा रहे हैं, और यह हमारे लिए भी एक भावुक पल है। हमने उन्हें देश के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक बनते देखा है, और हमें उनके सफर पर बहुत गर्व है।

# न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच मजेदार होंगे : रायन विलियम्स

**ऑकलैंड (एजेंसी)**



भारत के फॉरवर्ड रायन विलियम्स न्यूजीलैंड में खेलने के अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल भारतीय पुरुषों के देश के पहले दौरे की तैयारी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल टीम गुरुवार को ऑकलैंड के गो मीडिया स्टेडियम में दो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों में से पहले मैच में ऑल व्हाइट्स का सामना करने के लिए तैयार है। यह दोनों टीमों के बीच तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इससे पहले 1981 और 2018 में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं। यह दौरा भारतीय टीम के ज्यादातर सदस्यों के लिए नया है। विलियम्स ऑस्ट्रेलियाई क्लब पर्थ ग्लोरी के साथ अपने समय के दौरान न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं। 33 साल के इस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में पामर्स्टन नॉर्थ में वेलिंगटन फीनिक्स के खिलाफ ग्लोरी के 2-2 से ड्रॉ मैच में हिस्सा लिया था, जिसे 'डिस्टेंस डर्बी' के नाम से जाना जाता है। तस्मान में यात्रा करने की जरूरतों का अनुभव होने के कारण, वह लंबी यात्रा और समय के अंतर से आने वाली चुनौतियों को जानते हैं। विलियम्स ने कहा, 'हर बार जब मैं खेलने के लिए न्यूजीलैंड आया हूं, तो यह हमेशा मुश्किल रहा है क्योंकि यह हर चीज से बहुत दूर है। पर्थ से, यह बहुत दूर है। समय का अंतर भी एक ऐसी चीज है जिसे आपको मैनेज करना होता है।' ऑकलैंड भारत से साढ़े सात घंटे आगे है, इसलिए बॉडी क्लॉक में बदलाव को मैनेज करना टीम की पहली प्राथमिकताओं में से एक था। विलियम्स ने कहा कि उन्होंने यात्रा के दौरान एक प्लान्ड स्लीप रूटीन का पालन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच यात्रा करने के कई सालों के अनुभव का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, 'मेरा प्लान फ्लाइट के पहले हिस्से में सोने का था, जो मलेशिया के लिए था। मैं कुछ घंटे सोया, फिर जब तक हम यहां नहीं पहुंच गए, तब तक लगभग सोया ही नहीं। यह आपकी पूरी बॉडी क्लॉक को एक तरह से रीसेट कर देता है, इसलिए आप यहां आ सकते हैं, सीधे सो सकते हैं और पूरी रात सोने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा पहले भी कई बार किया है, इसलिए यह निश्चित रूप से ऐसी स्थितियों में मदद करता है।' मंगलवार को नॉर्थ हार्बर स्टेडियम आउटर ओवल में भारत के ट्रेनिंग सेशन के दौरान भारी बारिश हुई। विलियम्स, जो ऐसे माहौल के आदी हैं, उन्हें कुछ टीममेट्स की प्रतिक्रिया इस दौरान मजेदार लगी। उन्होंने मजाक में कहा, 'तेज बारिश, ठंड और गीली, कीचड़ वाली जमीन पर ट्रेनिंग करने के बाद, मुझे इसकी आदत हो गई है। लेकिन ये लड़के आए, और यह काफी मजेदार था। यह कूल रनिंग्स के किसी सीन जैसा था।' हालांकि, सभी ने इसका आनंद लिया। फुटबॉलर के तौर पर हम दुनिया के अलग-अलग मौसम, तापमान और हिस्सों में खुद को परखना चाहते हैं। यह सच में रोमांचक है।

## डब्ल्यूटीए फाइनल्स : नोस्कोवा ने गॉफ को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

**इंडियन वेल्स लिंडा (एजेंसी)** नोस्कोवा ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नोस्कोवा ने कोको गॉफ को 75 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। नोस्कोवा 2011 में पेट्रा क्वितोवा के बाद अपने पहले डब्ल्यूटीए फाइनल्स में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। डब्ल्यूटीए के आंकड़ों के अनुसार, वह 2024 में गॉफ के बाद अपने पहले दो राउंड-रॉबिन मैच जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी हैं और 2021 में एनेट कोंटावेइट के बाद ऐसा करने वाली पहली नंबर 8 सीड हैं। लिंडा नोस्कोवा ने पत्रकारों से कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं सेमीफाइनल में हूं।

मैच खत्म होने के ठीक बाद, मैं पहले से ही इस बात पर फोकस कर रही थी कि मैं दो दिन में जेसी (पेगुला) के साथ कैसे खेलूंगी। इसलिए मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला है। मैं अभी भी जीतना चाहती हूं। मैं अभी भी जो भी स्कोर, जो भी जीत मुमकिन हो, हासिल करना चाहती हूं। मैं यहां असल में मैच नहीं खेल रही हूं, इसलिए यह कुछ अलग नहीं होने वाला है। नोस्कोवा ने गॉफ को पांच बार ब्रेक किया, जिसमें शुरुआती सेट में चार बार शामिल हैं। उसने नौ में से पांच ब्रेक-पॉइंट मौकों को कन्वर्ट किया और गॉफ की दूसरी सर्व पर 75 प्रतिशत (24 में से 18) पॉइंट जीते। रिटर्न पर नोस्कोवा ने जो दबाव डाला, उससे उन्हें दोनों सेट में 4-1 की लीड बनाने में मदद मिली।

# अनुष्का सेन वायरल पोस्ट : 'इतना खूबसूरत दिखना अपराध है'; 24 साल की एक्ट्रेस ने दिए ऐसे पोज, दीवाने हुए यूजर्स



24 साल की अभिनेत्री अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह अपने फैंस को अपनी जिंदगी से जुड़ी हर अपडेट देती रहती हैं। कई बार अभिनेत्री विदेश में अपने टूर की और अपने माता-पिता के साथ तस्वीरें साझा करती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। अनुष्का सेन ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने सूरज की रोशनी में खूबसूरत पोज दिए हैं। अभिनेत्री ने ब्लैक स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना है। अभिनेत्री ने ऊपर से मरून दुपट्टा डाला है। उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस से पूरा किया है। कंगना रनौतः एक्ट्रेस ने सोनिया गांधी को कहा रहस्यमयी विदेशी नागरिक, गांधी परिवार के इतिहास पर साधा निशाना

**यूजर्स को पसंद आई तस्वीरें**

अभिनेत्री अनुष्का सेन ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'जब सूरज मेरे चेहरे को चूमता है।' अभिनेत्री की पोस्ट को कई यूजर्स ने लाइक किया है और कई फैंस ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा 'अन्नू के लिए लाल रंग।' एक और यूजर ने लिखा 'चमकता हुआ खूबसूरत चेहरा।' एक और यूजर ने मजाक में लिखा 'कोई पुलिस को बुलाओ। इतना खूबसूरत दिखना अपराध है।'

**कौन हैं अनुष्का सेन?**

4 अगस्त 2002 को जन्मीं अनुष्का सेन झारखंड के रांची से ताल्लुक रखती हैं। बचपन में ही वह अपने माता-पिता के साथ मुंबई में बस गईं। वह 'बालवीर', 'झांसी की रानी', 'फियर फैक्टरः खतरों के खिलाड़ी 11', और 'दिल दोस्ती डिलेमा' के लिए मशहूर हैं।

**अनुष्का सेन का वर्कफ्रंट**

अभिनेत्री को साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'एम आई नेक्स्ट' में देखा गया था। इसमें उन्होंने हनी नाम की 14 साल की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ और वह गर्भवती हो गई। गर्भपात कराने के लिए उसे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अभिनेत्री 2025 में रिलीज हुई सीरीज 'किल दिल' और 'है जुनून' का भी हिस्सा रहीं। **(एजेंसी)**

# देशभक्ति-बलिदान की कहानी लेकर आए सलमान, 'मातृभूमि' के ट्रेलर में दिखा उनका एक्शन अवतार

सलमान खान की मंगलवार को आने वाली फिल्म 'मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर जारी किया गया। यह फिल्म देशभक्ति, बलिदान और युद्ध की मानवीय कीमत की एक दमदार कहानी पेश करने का वादा करती है। ट्रेलर की शुरुआत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्रों में से एक में बर्फीले तूफान (एवलांच) के दृश्यों से होती है, जहां चीनी सैनिक 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (एलएसी) के भारतीय हिस्से में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। सलमान एक बेहद काबिल सैनिक के रूप में शानदार एंट्री करते हैं, जिनमें समझदारी और ताकत का बेहतरीन संतुलन है। इसके बाद ट्रेलर उनकी निजी जिंदगी की झलक दिखाता है, जिसमें अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी के रूप में नजर आती हैं, जो उन्हें मिशन पर भेजे जाने को लेकर चिंतित हैं। तब सलमान उन्हें समझाते हैं कि यह कोई गोलीबारी वाली लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि एलएसी पर आमना-सामना होने पर चीनी और भारतीय सैनिक बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा दोनों देशों के बीच हुए उन समझौतों की वजह से है, जिनका मकसद सैन्य तनाव को पूर्ण युद्ध में



बदलने से रोकना है।

ट्रेलर एक सैनिक के जीवन की झलक पेश करता है, जहां ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती और परिवार के साथ बिताया हर पल बहुत कीमती होता है। यह फिल्म युद्ध के मानवीय पहलू को दिखाती है, और उन लोगों के भावनात्मक बलिदानों को सामने लाती है जो देश की सेवा करते हैं, साथ ही उन अपनों के दर्द को भी दिखाती है जो उनका इंतजार करते हैं। सलमान खान अपने दमदार एक्शन अवतार में छा जाते हैं, जबकि चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ती है। फिल्म की खूबसूरती को इसके शानदार लोकेशन, बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और प्रभावशाली संगीत और भी बढ़ा देते हैं। फिल्म एक गहरा संदेश देती है कि युद्ध का कभी कोई सुखद अंत नहीं होता; इसमें दोनों तरफ जान-माल का भारी नुकसान होता है, इसके परिणाम युद्धक्षेत्र से कहीं दूर तक फैल जाते हैं और परिवारों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है और इसे 'सलमान खान फिल्म्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। **(एजेंसी)**



# गार्ड की मौत पर छलका दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया का दर्द, सुनाई आपबीती

टीवी की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने कुछ समय पहले एक बड़े हादसे का सामना किया था। दिवाली से ठीक पहले उनकी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेहद करीबी और भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड धनपत अंकल को हमेशा के लिए खो दिया था। इस दर्दनाक हादसे और अपने गहरे नुकसान को बयां करते हुए दिव्यांका ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर कर उस वक्त की आपबीती सुनाई। दिव्यांका ने अपनी बिल्डिंग में लगी आग और गार्ड धनपत की तस्वीर शेयर करते हुए उस खौफनाक रात की दास्तान साझा की। उन्होंने लिखा कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर की खामोशी दे जाते हैं। जब वे अपने दोनों बच्चों को पहली बार घर लेकर आए थे, तो उनका सबसे पहले प्यार से स्वागत करने और आशीर्वाद देने वालों में धनपत अंकल ही थे। वे चाहते थे कि बच्चे उनके साथ खेलते हुए बड़े हों, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्यांका ने बताया कि दिवाली से ठीक एक रात पहले उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी। उस शाम उन्हें बाहर निकलना था, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका जाना टलता रहा। इसी वजह से हादसे के वक्त पूरा परिवार घर पर मौजूद था और समय रहते खतरे को भांपते हुए वे बच्चों, परिवार और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल सके थे। शुरुआत में लगा कि सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में गार्ड धनपत के निधन की खबर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इस दुखद खबर का जिक्र करते हुए दिव्यांका ने लिखा, 'मैं और विवेक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम एक दोस्त के घर बैठकर बस यही दुआ कर रहे थे कि काश यह खबर झूठी निकले। दिवाली के बाद धीरे-धीरे बिजली, गैस और लिफ्ट की सुविधा बहाल हो गई थी, लेकिन पूरी विंग में सन्नाटा पसरा रहा। वजह सिर्फ बिल्डिंग का नुकसान नहीं, बल्कि एक कीमती जिंदगी का चले जाना था। उस आग ने हमारे दिल में एक ऐसा अंधेरा कर दिया, जिसे कोई रोशनी दूर नहीं कर सकती। दिव्यांका ने अपने नोट में भावुक होते हुए लिखा कि धनपत अंकल सिर्फ गार्ड नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा थे। उन्होंने लिखा, 'जब हमारे दोनों बेटे बड़े होंगे, तो हम उन्हें जरूर बताएंगे कि कैसे एक भले इंसान ने घर आते ही उन्हें आशीर्वाद दिया था। आपने हमें सिखाया कि किसी भी इंसान की मौजूदगी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पल आखिरी साबित हो जाए। **(एजेंसी)**



# 'रामायण : पार्ट 1' देखकर हेमा मालिनी हुईं हैरान, बोलीं- स्पेशल इफेक्ट्स देखकर थम सी गईं सांसें

अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हाल ही में फिल्म 'रामायणः पार्ट 1' देखी। फिल्म देखने के बाद वह खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाईं। उन्होंने न सिर्फ फिल्म के कलाकारों की जमकर सराहना की, बल्कि फिल्म की कहानी और सिनेमाघरों में दर्शकों को मिल रहे प्यार पर भी अपनी खुशी जाहिर की। हेमा मालिनी का कहना है कि यह फिल्म दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां वे खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'मैंने फिल्म 'रामायण- द मूवी' का नया वर्जन देखा। उन्होंने आगे लिखा, रामायण एक ऐसी कहानी है, जिसकी कहानी छोटे-छोटे बच्चों को भी पता है, इसलिए मैं बिना किसी उम्मीद के फिल्म देखने गई थी। मुझे लगा कि रामायण की कहानी में क्या ही नया डाल सकते हैं, लेकिन फिल्म देखकर मैं हैरान रह गई। इसकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। इसके स्पेशल इफेक्ट्स इतने जबरदस्त थे कि मेरी सांसें थम सी गईं। फिल्म में कलाकारों का चुनाव भी बिल्कुल सही किया गया है। अभिनेत्री ने दर्शकों के रिएक्शन के बारे में बात करते हुए लिखा, दर्शकों का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे वो किसी और ही दौर में पहुंच गए हों और कहानी के साथ-साथ खुद भी उसमें शामिल हो गए हों। सच में, फिल्म में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही सबसे बड़ा फर्क लेकर आया। भारतीय दर्शकों के लिए यह एक बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव था। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म 'रामायण' को सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। **(एजेंसी)**

# सरकार ने लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर लगाई रोक

**नई दिल्ली (एजेंसी)**

सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है।

अधिसूचना के मुताबिक, 'आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, जो बिना छांटे हुए हैं और



जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास), की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी।

यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी। 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन) शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है।

# भाई दूज के दिन फीकी पड़ी सोने की चमक, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

**नई दिल्ली (एजेंसी)**

घरेलू सर्राफा बाजार में भाई दूज के दिन सोने के भाव में कमजोरी नजर आ रही है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना आज 1,770 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,960 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने के भाव में 450 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 490 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह चमकीली धातु आज भी सोमवार के भाव पर ही कारोबार कर रही है। कीमत में बदलाव होने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,120 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,30,790 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,04,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,42,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,42,730 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

# मुंबई हवाई अड्डा टी-1 पुनर्विकास : अंतरराष्ट्रीय यातायात का करीब 91% हिस्सा रहेगा अप्रभावित

**मुंबई (एजेंसी)**

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात का करीब 91 प्रतिशत हिस्सा टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के दौरान अप्रभावित रहेगा। ग्रीष्मकालीन 2027 के कार्यक्रम के तहत 50 में से 39 अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियां हवाई अड्डे से अपना परिचालन जारी रखेंगी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि शेष 11 विमानन कंपनियां चुनिंदा गंतव्यों के लिए रोजाना कुल करीब 16 उड़ानें संचालित करती हैं। ये कंपनियां मार्च



2027 के अंत से अपनी प्रभावित उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) पर स्थानांतरित कर सकती हैं।

एमिरेट्स, एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, श्रीलंकन एयरलाइंस, थाई एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और टर्किश एयरलाइंस सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियां सीएसएमआईए के टर्मिनल-2 से अपना परिचालन जारी रखेंगी। उन्होंने बताया कि 1964 में शुरू किए गए टर्मिनल-1 का पुनर्विकास मुख्य रूप से संरचनात्मक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इन चिंताओं को 2017 में स्ट्रक्चवेल और 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे द्वारा किए गए ऑडिट में सामने लाया गया था। उन्होंने कहा कि इन ऑडिट के निष्कर्षों में छह दशक पुराने इस जर्जर परिसर को आधुनिक बुनियादी ढांचे से बदलने की जरूरत रेखांकित की गई है।

# व्हाट्सएप योजना : एआई, डिजिटल पेमेंट और बेहतर मैसेजिंग की तैयारी

**नई दिल्ली (एजेंसी)**

व्हाट्सएप अपनी सेवाओं को मैसेजिंग से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड कुणाल शाह, जिन्होंने जून 2026 में यह जिम्मेदारी संभाली थी, ने मंगलवार को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट और बेहतर कम्युनिकेशन फीचर्स उनकी तीन मुख्य प्राथमिकताएं हैं।

शाह ने पहले चार महीने उपयोगकर्ताओं की उम्मीदों को समझने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में बिताए, जहां मैसेजिंग सर्विस में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म के भविष्य के रोडमैप के बारे में बताया। वर्तमान में, दुनिया



भर में व्हाट्सएप के तीन अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। 'एक्स' पर एक पोस्ट में, शाह ने कहा कि कंपनी का फोकस लोगों को एक-दूसरे के करीब रहने में मदद करने और एप्लिकेशन के भीतर रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने पर होगा।

उन्होंने व्हाट्सएप को एक ऐसी 'साझा भाषा' के रूप में बताया, जिसका इस्तेमाल अरबों लोग करते हैं। यहां लोग टेक्स्ट मैसेज, वॉयस नोट, स्टिकर और वीडियो के जरिए बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं व्हाट्सएप को एक ऐसी साझा भाषा की तरह देखता हूं, जिसे 3 अरब से ज्यादा लोग बोलते हैं।

कभी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी अपने माता-पिता को वॉयस नोट भेजते हैं, किसी बहस को खत्म करने के लिए स्टिकर का उपयोग करते हैं, या रात के खाने के बाद 'आज का डिनर बहुत मजेदार था' जैसा मैसेज भेजते हैं। भाषा हमारे हर काम के मूल में है। हम पत्र लिखते हैं, कहानियां सुनाते हैं, काम पूरे करते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। अक्सर इन सब की शुरुआत एक व्हाट्सएप चैट से ही होती है। शाह ने आगे कहा, पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने उपयोगकर्ताओं की बातें सुनीं और समझने की कोशिश की कि वे हमसे क्या चाहते हैं।

मुझे जो समझ आया, वह बहुत सरल है- लोग चाहते हैं कि हम उन्हें उनके अपनों के करीब रहने में मदद करें और व्हाट्सएप पर उनके काम आसानी से पूरे हो सकें। इसलिए, हम इसी दिशा में काम करेंगे। पहली प्राथमिकता बातचीत को और अधिक प्रभावी और इस्तेमाल में आसान बनाना होगा। व्हाट्सएप अपनी संचार आदतों में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए वॉयस नोट, ग्रुप चैट, स्टिकर और वीडियो इंटरैक्शन जैसे फीचर्स को बेहतर बनाने की योजना बना रहा है।